हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 जनवरी, 2006

खण्ड–1, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 16 जनवरी, 2006

	पृष्ठ संख्या
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3) 1
वाक आउट	(3) 1
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(3) 1
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3) 2
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(3) 2
वाक आउट	(3) 3
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(3) 4
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	(3) 13
वाक आउट	(3) 13
मन्त्री द्वारा वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(3) 13
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(3) 14

मूल्य :

पृष्ठ संख्या

रूल्स कमेटी की रिपोर्ट मेज पर रखना (3)51

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में संशोधनों की स्वीकृति (3)51

विधान कार्य—

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असेम्बली (अलाऊंसिज एंड पैंशन ऑफ मैम्बज) अमैंडमैंट बिल, 2006 (3)६-

वाक आउट

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाऊंसिज एंड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2006(पुनरारम्भ)

HV8 / Lib / (9)

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 16 जनवरी, 2006

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात् हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under rule 15.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

वाक आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री द्वारा सदन की कार्यवाही में शामिल होने के विरुद्ध एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आऊट करते हैं। क्योंकि इनका नाम वोल्कर रिपोर्ट द्वारा शुरू हुए विवाद में उजागर हुआ है।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोक दल के सभी सदस्य सदन से वाक आऊट कर गये।)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule

[Mr. Speaker]

'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under rule 16.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, discussion on the Governor's Address will be resumed.

श्री एस. एस. सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर साहब, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। (शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होने से पहले सरकार स्टेटमैंट दे कि रतिया तहसील में भूना पुलिस स्टेशन के एरिया में गांव कुनाल के दलित परिवारों के घर क्यों उजाड़े गए? उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये अपना समय भूल गये क्या? इन्होंने तो गांव के गांव उजाड़े थे। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब तो उस

कहावत को चरितार्थ कर रहें हैं कि छाज तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या ये दुलीना कांड को भूल गये कि वहां पर किस तरह से गरीब बाल्मीकियों और रामदासियों के बच्चों की हत्या इनकी सरकार के समय में की गई थी? (शोर एवं व्यवधान) वहां पर गरीब हरिजनों की हत्याएं इनकी सरकार के समय में बंदूक की संगीनें चुभो-चुभो कर की गई थीं। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि वहां पर जो निर्दोष लोग थे उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये थे। (शोर एवं व्यवधान) पुलिस के जिन कर्मचारियों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया था उनको इनके नेता और मुख्यमंत्री ने बचाने का काम किया था। उस समय इन्दौरा साहब हुड्डा साहब के पास आते थे और कहा करते थे कि हुड्डा साहब, हमें बचाओ हमारे पर जुल्म हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय में दुलीना और हरसौला में गरीब हरिजनों के घर उजाड़े गये और निसिंग में बाल्मीकियों के घरों को आग लगाई गई थी। उस समय इन्दौरा साहब आप हुड्डा साहब को संसद के अलग-अलग कोनों में ले जा करके कहा करते थे कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दलितों का भक्षक है उससे हुड्डा साहब आप ही बचा सकते हैं। इनको उस राक्षस रूपी सरकार से बचाया गया और आज ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं। स्पीकर सर, सरकार की तरफ से मैं इस हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी मामला हो सरकार पहले भी उसकी जांच करके कार्यवाही करती आई है और इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर केवल बहिर्गमन के लिये ग्राउंड बनाने के लिये कुछ करना हो तो अलग बात है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आपने कुछ लिखकर तो दे नहीं रखा है इसलिये अभी आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न एवं शोर) इन्दौरा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, आपने विपक्ष के साथियों को बोलने का मौका दिया। (विघ्न) 48 मिनट्स तक इनके सदस्यों को बोलने का मौका दिया हालांकि इनकी संख्या के मुताबिक इनको 18 मिनट बोलने का समय मिलना चाहिये था इससे ज्यादा इनका समय नहीं बनता है। इन्दौरा साहब, बोलते हुये कुछ खास कह नहीं पाये कभी ये पसीना पोंछते थे, कभी रूमाल निकालते थे और यहां तक कि अपना भाषण तक भूल गये। ये लोग आज फिर सदन की कार्यवाही के अन्दर विघ्न डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इनका लक्ष्य केवल आज के लिये खबर बनाना है अथवा बहिर्गमन करना है तो अच्छा होगा कि कम से कम ये सदन का समय तो नष्ट न करें। (विघ्न एवं शोर)

वाक आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर) जिला फतेहबाद की तहसील रतिया में भूना पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अन्तर्गत कुनाल गाँव में हरिजनों

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
पर जो अत्याचार हुआ है उस के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Indora, Please behave properly (Interruptions) Please take your seats. (Interruptions) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। (शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं हम इसके विरूद्ध एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन से वाक आऊट कर गये।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री एस० एस० सुरजेवाला : स्पीकर साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में यह कहना चाहूँगा कि एक साल से कम समय में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने हरियाणा में एक दर्जन के करीब मील के पत्थर रखे हैं जो कभी भी इतिहास से भुलाये नहीं जा सकेंगे। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहता हूँ। जो स्टैप्स सरकार ने दस महीने के थोड़े समय में लिये हैं उनसे हरियाणा की ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है। इस सरकार के नेतृत्व ने ग्रोथ विद इक्वैलिटी के साथ हिन्दुस्तान में हरियाणा को नम्बर एक प्रान्त बनाया है। मैं सरकार से पूरी उम्मीद रखूंगा कि यह जो ग्रोथ के साथ प्रति व्यक्ति इन्कम है, इक्विटेबल तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की सरकार कोशिश करेगी। हालांकि इस दिशा में सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं खासतौर से महिलाओं और लड़कियों के लिये, दलितों के लिये, गरीबों के लिये, किसानों के लिये एक दर्जन से भी ज्यादा प्रोग्राम और स्कीम्ज सरकार ने शुरू की हैं। भय और भ्रष्टाचार को इस प्रान्त से खत्म किया है। पिछले साढ़े पाँच साल की सरकार में यहां पर सबसे ज्यादा जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ था उसको इस सरकार ने खत्म किया है। सरकार का बिजली का 1600 करोड़ रुपये का जो ऐरियर था जिसको किसान कभी उतार नहीं सकते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कांस्टीच्युएंसी में एक गाँव है। दस करोड़ रुपये अकेले इस एक गाँव के लोगों ने बिजली के बिल देने थे। पूरे गाँव की सारी जमीन बेचकर भी वे इतने रुपये के बिल अदा नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि उनको पूरी उम्र के लिये कभी बिजली नहीं मिलनी थी। वे लोग बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से और भी बहुत से गाँव हैं जहां पर किसानों को सरकार की इस पॉलिसी से बहुत राहत मिली है। इस सरकार द्वारा नई इण्डस्ट्रियल और नई लेबर नीति को लाकर कई हजार करोड़ रुपये की आय का रास्ता प्रशस्त किया गया है। इन पॉलिसीज के द्वारा एक्सप्रैस वेज और हाईवेज बनाने के लिये बहुत बड़ा काम किया गया है। सरकार ने इसके लिये काम शुरू भी करवाया है। देश में गन्ने का सबसे ऊँचा भाव भी सरकार

ने किसानों को दिया है लेकिन इसी स्थान पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गन्ने का सबसे ऊँचा भाव तो दिया है और किसानों को उससे फायदा भी हुआ है लेकिन अगर आप आंकड़ें देखें तो आंकड़े यह बताते हैं कि हरियाणा में जो प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार है वह 200 क्विंटल के करीब है जबकि ब्राजील और दुनिया के दूसरे कई मुल्कों में गन्ने की पैदावार 800 क्विंटल प्रति एकड़ है। इस तरह से यह वैल्यू ऐडेड प्रोग्राम है। हमारे यहां और दूसरे मुल्कों की गन्ने की पैदावार में बहुत अंतर है। अगर यह पैदावार बढ़ायी जाये तो इससे बहुत छोटे किसानों का कल्याण हो सकता है और यह कदम कल्याणकारी साबित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, गन्ने की रिसर्च हरियाणा में अभी भी बहुत पुरानी है। देश में भी गन्ने की रिसर्च बहुत पुरानी है। आई.सी.ए.आर. और एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को चाहिये कि वह गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ायें ताकि वाकई सही मायनों में जो सरकार ने गन्ने का ऊँचा भाव दिया है उसका और ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। अध्यक्ष महोदय, स्पैशल इकोनोमिक जोन इस प्रांत की तरक्की के लिये सरकार ने स्थापित किये लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी इस बारे में कहा था और संक्षिप्त में अब भी मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार जो यह स्पैशल इकोनोमिक जोन बनायेगी तो सरकार को इनके अन्दर गाँवों में बसने वाले लोगों के लिये भी इनके पूरे लाभ पहुँचाने का इंतजाम करना चाहिये। वे लोग भी सारे कार्यक्रम में समायोजित होने चाहियें। उनके मकान भी दोबारा से बनाने चाहिएं और उनके बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनकी जिंदगी को यूजफुल बनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों के लिये सरकार को पहले से ही तैयारी करनी चाहिये। सरकार ने लड़कियों को भी बहुत रियायतें दी हैं। मेल और फीमेल रेशो को कम करने के लिये सरकार ने बहुत सी रियायतें दी हैं जोकि बहुत सराहनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ओम प्रकाश चौटाला के भ्रष्टाचार की इंक्वायरी सी.बी.आई. को सौंपने के लिये भारत सरकार को लिखा है। मुझे यह भी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार भारत सरकार को प्रैस करेगी कि जल्दी ही सी.बी.आई. के सीनियर मोस्ट और निष्पक्ष अधिकारी से यह इंक्वायरी करवायी जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हरियाणा के अपने अलग हाई कोर्ट की स्थापना करने के लिये भी असैम्बली से प्रस्ताव पास करवाया है। इस तरह से मैं समझता हूं कि इस सरकार द्वारा एक साल से कम अर्से में आज तक जो एक दर्जन मील के पत्थर यानी माईल स्टोन रखे गये हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं। हमको उम्मीद है कि इनको पूरा करवाने के लिये सरकार जिस तत्परता से लगी है वह जल्दी ही इनको पूरा करवाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना है इसलिये मुझे इस बात का अहसास है इसके अलावा बाकी मैम्बर्ज भी बोलना चाहेंगे इसलिये मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो मैं किसानों की आत्महत्या के बारे में कहना चाहूँगा। किसानों की आत्म हत्याएं अपने आप में कोई सवाल नहीं है बल्कि किसानों की जिंदगी में, उसके व्यवसाय में और उसके रोजगार में बहुत भारी दिक्कतों का कल्मीनेशन है। अगर कोई सबसे भारी दिक्कत समराइज की जाये और अगर कोई यह कहे कि एक नुक्ते में, एक बात में इसको बताया जाये कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं और उसको रोका कैसे जा सकता है तो यह बताना आसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नैशनल कमीशन ऑन फार्मर्ज की सैकेंड रिपोर्ट में भी यह बात कही गयी है। उन्होंने कहा है कि—

"Main cause singled out by experts is the prevalent capital-

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

intensive farming, that, they say, has led farmers to a debt-trap and eventually to death."

स्पीकर साहब, इस वक्त कर्जे की व्यवस्था इस प्रकार है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपका प्वायंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि सदन के रूल्ज के हिसाब से यह बात है कि जब भी मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट में नये मंत्री इंडैक्ट करते हैं तो he should introduce the Ministers in the House.

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, क्या आप जानते नहीं हैं। You were cordially invited in the oath ceremony. (Interruptions). डॉ० साहब, अगर आप ओथ के समय नहीं आये तो फिर यहां पर क्यों बात कर रहे हैं?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जाने था न जाने लेकिन नियमानुसार हाउस में इनको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिये। मैं हाउस में रूल की बात कर रहा हूँ।

Mr. Speaker : Please take your seat. (Interruptions). Do not waste the time of the House. आप हाउस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज आप बैठ जायें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, बड़े खेद की बात है कि इस छोटी सी बात और प्रोसीजर की तरफ ही ध्यान नहीं दिया गया। सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए इंट्रोडक्शन होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी इंट्रोड्यूस कराते तो क्या बात थी। मैं सदन की परम्पराओं के अनुरूप बात कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि आप ये बात मोबाइल पर पूछ कर आए हो।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) स्पीकर साहब, इनका तो वह हिसाब है कि चोर की मां खुलड़ी में मुंह देखै और फिर रौवे। ये हर बात पर अपनी बात भूल जाते हैं और फिर एक विशेष पूर्व मंत्री को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं। वे इन्हें ब्रीफ करते हैं। मैं तो इनसे कहता हूँ कि कुछ अपनी बुद्धि लगाकर काम किया करें। सम्पत सिंह जी की बुद्धि से काम नहीं चलना।

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Speaker Sir, I want your ruling that what is point of order ? He should know that is point of order ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Speaker Sir, he should know the rules.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि किसान की आत्महत्या के बहुत से कारण हैं, बहुत सी वजह हैं। इनकी वजह से ही ऐक्सट्रीम स्टैप किसान को, खेतिहर मजदूर को उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं कर्ज की व्यवस्था के बारे में चर्चा

कर रहा था लेकिन ये विपक्ष के साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इनकी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये किसान के दुश्मन हैं, हमदर्द नहीं हैं। कर्ज की जो प्रथा है, प्रणाली है मैं उसके बारे में कह रहा था कि नाबार्ड 4 परसैंट पर राष्ट्रीयकृत बैंकों को और कोऑपरेटिव बैंकों को जिसमें लैंड डिवैलपमैंट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं, वो किसान को खेती में देने के लिये इनको लोन देता है। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात है, जिस वक्त इन बैंकों को इंदिरा गांधी जी ने नैशनेलाइज किया था, तब यह फैसला हुआ था कि ये टोटल लोनिंग का कम से कम एक साल में जो एडवांस राशि देंगे उसमें से कम से कम 18 प्रतिशत किसानों को खेती के लिये देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक भी इस रकम को 14 परसैंट से ज्यादा ऐक्सीड नहीं किया है। आज भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे किसान और खेतिहर मजदूर को 18 परसैंट नहीं दे रहे हैं। मेरी मांग है कि हरियाणा सरकार भारत सरकार को लिखे कि किसान को टोटल लोनिंग में से जो 18 परसैंट देना था उसके बारे में मैं तो यहां तक कहूँगा कि इसको बढ़ाकर कम से कम 30 प्रतिशत करवाया जाये और इसको सख्ती से लागू करवाया जाये। जो राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसा नहीं करते उनके मैनेजर बहुत ही खुश होकर टैलीफोन करके लोगों को बुलाते हैं कि आप हमारे से कार के लिये चार परसैंट और छह परसैंट ब्याज पर कर्ज ले लो। एयर कंडीशन के लिये, कलर टी.वी. के लिये, कोठी बनाने के लिये वे बुलाकर के कर्ज देते हैं लेकिन जब किसान और मजदूर कर्ज के लिये जाते हैं तो 100 तरह की अड़चनें अड़ाई जाती हैं। मैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहना चाहूँगा कि आज सरकार ने कर्ज की उस ब्याज दर को जो पहले 14 परसैंट पर होती थी, 17 परसैंट पर होती थी वह घटाकर 9-10 परसैंट की है। सरकार की मजबूरी यह है कि थ्री टायर बैंक हैं। नाबार्ड के बाद स्टेट लैवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जिला सहकारी बैंक हैं। प्राइमरी बैंक उनको कहते हैं जो कोऑपरेटिव भी हैं और लैंड डिवैलपमैंट बैंक भी हैं। गाँव की जो सोसायटी है उसको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी कहते हैं और मिनी बैंक भी कहते हैं। नाबार्ड से चार परसैंट ब्याज दर पर लोन आकर फिर 3 परसैंट स्टेट लैवल पर और तीन परसैंट जिले या सब-डिवीजन लैवल पर इस प्रकार टोटल 10 परसैंट के ऊपर ब्याज जाकर टिकता है। मेरा सुझाव है कि अगर किसान को राहत देनी है तो इन दोनों स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सब-डिवीजन और जिले पर जो बैंक हैं, उनको अबोलिश कर देना चाहिये। इनकी कोई जरूरत नही है। जो मिनी बैंक हैं जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी हैं इसको रूरल बैंक बना देना चाहिये और इसकी मैम्बरशिप नॉन-मैम्बर और सभी के लिये खोल देनी चाहिये ताकि गाँव में जो सरप्लस पैसा है या फिर किसान अपनी फसल को बेचकर जो पैसा आज आढ़ती के पास जमा करके आता है वह इस बैंक में जमा कर सके क्योंकि आढ़ती किसान को कोई ब्याज नहीं देते। किसान को इस बात का ज्ञान नहीं है। इसलिये इन सोसायटियों को रूरल बैंक बना देना चाहिये। नाबार्ड सीधा इन बैंकों को कर्जा दे सकता है। नाबार्ड तो 4 प्रतिशत ब्याज लेता है इसलिये वह 4 प्रतिशत की बजाये 6 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्जा दे सकता है, जो दलित या भूमिहीन लोग हैं उनको 5 प्रतिशत ब्याज पर पैसे दे सकता है। मेरी मांग यह है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट लैंड डिवैल्पमैंट बैंकों का सिवाये खर्चा करने के कोई फंक्शन नहीं है लेकिन इन बैंकों के मल्टी नैशनल कम्पनियों की तरह बड़े-बड़े रैस्ट हाउस हैं और इनके

[श्री एस. एस. सुरजेवाला]

जो डायरैक्टर हैं वे देश-विदेशों की सैर करते हैं और मोट-मोटे भत्ते लेते हैं। यह सब किसान के सिर पर से जाने लग रहा है। ऐसे ही स्टेट में डिस्ट्रिक्ट और सब-डिवीजन लैवल की इन बैंकों की ब्रान्चीज हैं उनका 3-4 प्रतिशत ब्याज का खर्चा ज्यादा और पड़ता है। नाबार्ड इन गाँवों के बैंकों को कर्जा दे सकता है। जो गाँव के मिनी बैंक और ये कोऑपरेटिव बैंक हैं इनमें अनसक्रुप्लस आदमी, बिना पढ़े-लिखे आदमी और सेमि-लिट्रेट सैक्रेटरी किसानों को लूटते हैं। इस बारे में आप सभी को विदित है इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। दूसरा मैं कर्जे के बारे में यह कहना चाहूँगा कि जिस समय ज्वाइंट पंजाब था उस वक्त की सरकार में चौधरी छोटू राम जी रैवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने इस प्रकार के कानून-कायदे बनाये थे कि जो प्राईवेट लोगों का किसानों के सिर पर कर्जा था उनको राहत देने का हर जिले में रिकंसीलिएशन डेट बोर्ड बनाये थे। इस बारे में एक सुझाव यह है कि जो आढ़ती लोग और प्राईवेट लोग किसान को और खेत मजदूर को कर्जा देते हैं उनकी ब्याज दर 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक होती है। बहुत से स्टेट में और बहुत सी जगह तो यह दर इतनी ज्यादा है कि किसान और खेत मजदूर की आत्महत्या और मरने का यह सबसे बड़ा कारण बनती है। कोऑपरेटिव बैंक की ब्याज की दर 6 प्रतिशत से ज्यादा न हो और जो बैंकिंग करते हैं या लोनिंग करते हैं जिनको इनफोरमल बैंकिंग कह सकते हैं उनकी दर को सरकार को रैगूलेट करना चाहिये। उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी होनी चाहिये। जो आढ़ती पैसे देते हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी होनी चाहिए। उनको डाक्यूमैंटेशन रखने चाहियें और लोन देते समय बाकायदा रिसीट देनी चाहिये कि इतना पैसा कर्जे के रूप में दिया गया है। जो कर्जा देते हैं उसके सारे रजिस्टर्ड डाक्यूमैंट होने चाहियें और सरकार को उनके ब्याज को समय-समय पर रैगूलेट करते रहना चाहिये। ऐसा न हो कि 45, 35, 25 प्रतिशत की दर से ब्याज किसानों से वसूल करते रहें। किसान इतनी दर का ब्याज कभी नहीं दे सकता इसलिये इस दर को सरकार को रैगूलेट करना चाहिये और जो पहले से ही कर्जे दिये हुये हैं उनको सैटल करने के लिये हर जिले में सैटलमैंट बोर्ड बनाया जाये। इसी प्रकार से कर्जा न देने की वजह से किसानों की गिरफ्तारी, किसानों की जमीन की नीलामी लैंड डिवलैपमैंट बैंक द्वारा और नैशनलाईज्ड बैंकों द्वारा की जाती है। ये दोनों काले कानून खत्म किये जायें। मुझे पूरी उम्मीद है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जिन्होंने अभी तक बहुत इन्कलाबी फैसले किये हैं, किसान और गरीब के हित के लिये वह इनको एक मिनट के लिये भी नहीं रहने देंगे और उनको कानून की किताब से बाहर निकाल कर फैंकेंगे। किसानों और गरीबों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिये। जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि कोई किसान, खेत-मजदूर और गरीब ब्याज के डर से मरने वाला नहीं है। एक बात बिजली के बारे में कहकर मैं अपना स्थान ले लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में भी और पूरे देश में बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। आज से 80 साल पहले 1917 में जब रूस में क्रांति आई थी तो क्रांति के जो सरगना मिस्टर लेनिन थे उन्होंने एक बात कही थी--

" Electrification of agriculture and industry will emancipate the labourer from the arduous works and give him a life equivalent to all other people who are working in the offices." बिजली का आज इतना महत्त्व है कि बिजली से ड्रैजरी, बिजली

से गंदगी, बिजली से पसीना और बिजली से मेहनत ये सारी बातें आसान हो जाती हैं। आज बिजली नसैसिटी है। आज बिजली कोई लग्जरी नहीं है और बिजली के बिना आप आज कुछ नहीं कर सकते इसलिये मैं कहूँगा कि हरियाणा ने जहां बहुत सी प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं, बिजली की प्राथमिकता को नम्बर एक पर निर्धारित किया जाये। पहले बिजली का महकमा मुख्यमंत्री जी के पास था लेकिन अब यह महकमा हमारे साथी और कुलीग श्री विनोद शर्मा जी के पास है। विनोद शर्मा जी पढ़े-लिखे, समझदार, बुद्धिमान हैं और उनमें क्षमता है लेकिन बिजली अकेला कोई पावर स्टेशन, थर्मल प्लांट या हाइड्रो नहीं है। एनर्जी में आज 3-4 बातें और भी शामिल हैं जैसे अनकन्वैंशनल एनर्जी और उसके पार्ट आदि। मैं यह कहना चाहूँगा कि विनोद शर्मा जी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट से एक असिस्टैंस भी दिया जावे। वैसे तो शर्मा जी बिजली के फुल फलैजड मंत्री रहें उनको असिसट करने के लिये एक आदमी हो ताकि एनर्जी के जो दूसरे सोर्सिज हैं जैसे कोल, पैट्रोलियम, एयर एनर्जी और सन एनर्जी उनकी तरफ भी वे ध्यान दे सकें। बिजली की कमी को all out assort करनी चाहिये। मैं सरकार से एक बात और कहूँगा चाहे वह बात अनपापुलर है कि मंदिर में कोई व्यक्ति गुलदाना या पतासे का प्रसाद लेकर जाता है और जब वह वापिस आता है तो बच्चों की लाइन लगी होती है और वह व्यक्ति उन बच्चों के हाथ में एक-एक पतासा रखता जाता है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय,मैं 5 मिनट और लूंगा। मैं यह कह रहा था कि बच्चों के हाथ में पतासा रखने का कोई फायदा नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला ने वोट लेने के लिए जाते-जाते बेरोजगारी भत्ता अनाउंस कर दिया। मैं समझता हूँ कि इस बेरोजगारी भत्ते की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात इससे बनने वाली नहीं है। बेरोजगारी को अटैक करना है तो अलाउंस देकर बेरोजगारी अटैक नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बुढ़ापा पैंशन है लेकिन यह पैंशन उन लोगों को क्यों मिले, जिनके पास 10-10, 20-20 किल्ले जमीन है, जिनके पास दुकानें हैं, जिनके पास रोजगार हैं और जिनके बच्चे गजटिड ऑफिसर्ज लगे हुये हैं। यह पैंशन तो केवल सोशली वीकर्स लोगों को, विधवाओं को और उन विधवाओं को जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है और अपंग लोगों को जिनके पास आमदनी का स्रोत नहीं है उनको मिलनी चाहिये। इसी प्रकार से इस तरह की और भी बहुत सी स्कीमें हैं जो उपयोगी नहीं हैं उनको खत्म करके उस पैसे को बचाकर बिजली की पोजीशन सुधारने में लगाने चाहियें। हमारे जो थर्मल प्लांट लगे हुये हैं वहां कोयला 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर दूर से आता है और कोयला ट्रक या ट्रेन से आता है चूंकि आज किराये बहुत ज्यादा बढ़े हुये हैं इसलिये इतनी दूर से कोयला आने के कारण कोयला थर्मल प्लांट में बहुत महंगे रेट पर पहुँचता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को पिट हैड यानि जहां कोयले की खानें हैं वहां थर्मल प्लांट लगाने चाहिएं। असाम और दूसरी स्टेटस जहां कोयला पैदा होता है या तो वहां थर्मल प्लांट लगाए जाएं या जो वहां आलरेडी थर्मल प्लांट लगे हुये हैं उसमें हिस्सा कर लें तो यह बैस्ट पोलिसी होगी। आलरेडी जो कैरियर लाइनें बनी हुयी हैं सरकार उन लाइनों के द्वारा बिजली भी हरियाणा में ला सकती है जिससे हमें उपयोगी और सस्ता कोयला मिल सकता है। इसी प्रकार हिमाचल

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

और कश्मीर में हाइड्रो बिजली के बड़े पोटैंशियल हैं उनके साथ सरकार हिस्सेदारी करे या चाहे उनके साथ एग्रीमैंट करे कि अगले पांच साल के लिये आप अपनी सरप्लस बिजली हमें दो। इसके अतिरिक्त उनके बिजली के उत्पादन के लिये जो नये हाइड्रो प्रोजैक्ट लग रहे हैं उनमें अपना हिस्सा डालना चाहिये। इसी तरह से सरकार को अपने ट्रांसफार्मर बनाने चाहियें ताकि रोज-रोज की समस्या से हमें निजात मिले। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनको सरकार जानती है। मेरी तो दरखास्त यही है कि इन समस्याओं को प्राथमिकता पर यदि हम दूर कर देंगे तो जो बाकी अच्छे काम सरकार ने किये हैं उनके साथ ये कार्य सोने पर सुहागे की तरह होंगे। धन्यवाद।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की जो पिछली अचीवमैंट्स रही हैं, उन पर प्रकाश डाला है और सरकार भविष्य में क्या करने जा रही है उन कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में लोगों का कानून व्यवस्था पर से विश्वास ही उठ गया था। चारों तरफ डर और भय का वातावरण हरियाणा प्रदेश में हो गया था और हरियाणा प्रदेश से कारखानों का पलायन शुरू हो गया था। उस समय हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत पुअर थी और बिहार के बाद हरियाणा का दूसरा नम्बर गुण्डागर्दी में हो गया था। प्रदेश के लोग डर और भय की जिंदगी जी रहे थे। हमारी सरकार ने आते ही कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में ठीक की और लोगों का विश्वास बहाल किया। जो मशहूर बदमाश हरियाणा प्रदेश में पिछली सरकार के समय थे वे हरियाणा प्रदेश को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं और जो बदमाश यहां बचे हैं वे इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या उनको पुलिस पकड़ कर जेलों में डाल रही है क्योंकि हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह उनसे कोई समझौता नहीं करेगी क्योंकि हमारी सरकार को अपने नागरिकों की पूरी चिंता है। अब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत से बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने हरियाणा में कारखाने लगाने की बात कही है और सरकार उनको यहां लाने के लिये इण्डस्ट्रियल पॉलिसी बना रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में बात करना चाहूँगा। यहां पर बिजली के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बिजली के बकाया बिलों को भरना किसानों के बस की बात नहीं थी। कुछ लोगों ने अपनी राजनैतिक रोटियां पकाने के लिये किसानों को गुमराह किया था कि वे बिजली के बिल न भरें, जब उनकी सरकार आयेगी तो वे माफ कर देंगे। उनकी सरकार भी आई और पाँच साल तक चली लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों ने लम्बे समय तक ऐजीटेशन भी किया और हाईवे भी जाम किया और बहुत से किसान मारे भी गये लेकिन पिछली सरकार ने किसानों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब की सरकार ने आते ही वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चुनाव प्रचार के समय हमारी तरफ से न तो किसी ने कोई वादा किया था कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे लेकिन हमारी सरकार ने आते ही किसानों के बकाया बिजली के बिल माफ किये। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार भी इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि बिजली की समस्या को दूर किया जा सके और

हमारी सरकार भी बिजली की समस्या को प्रदेश से दूर करने के लिये प्रयत्न कर रही है। नये-नये थर्मल प्लांट्स की आधारशिला हमारी सरकार ने रखी और उनको बनाने का समय निर्धारित किया है। पिछली सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे ध्यान है कि जब पहली बार मैं इस सदन में चुनकर आया था उस समय 1982 में पूरे हरियाणा प्रदेश को 75 लाख यूनिट बिजली की जरूरत थी और आज के दिन प्रदेश की 5000 लाख यूनिट से भी ज्यादा की बिजली की जरूरत है। समय के साथ इस जरूरत को पूरा करना चाहिये था। आज हमारी सरकार इस जरूरत को पूरा करना चाहती है और इस समस्या को दूर करने के लिये पूरी तरह गंभीर है। केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी विद्युत परियोजना शुरू की है जिसके तहत 90 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देगी और 10 प्रतिशत पैसा हरियाणा सरकार देगी। जिसके तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू एरिया के लिये अलग से बिजली दी जाएगी। इस बारे में सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना को सरकार रैगूलर मोनीटर करती रहे ताकि यह परियोजना जल्दी पूरी हो सके और गाँव के लोगों को बिजली की समस्या न रहे। इसी तरह से महिलाओं के उत्थान के लिये, लड़कियों के उत्थान के लिये बहुत अच्छे-अच्छे स्टैप्स सरकार ने बड़े जोश के साथ उठाये हैं ताकि हमारा प्रदेश तरक्की कर सके। स्पीकर सर, हुड्डा साहब जब विपक्ष के नेता थे उस समय हमने जो लड़ाई लड़ी उसमें आप भी शामिल थे और हुड्डा साहब ने भी शिरकत की थी। लोगों में पूरी एक पीढ़ी के खिलाफ भेदभाव का दर्द रहा है। हरियाणा बनने के बाद विकास कार्यों के लिये बजट में भेदभाव बरता गया। चीफ मिनिस्टरों ने अपने इलाकों से बाहर निकल कर कम ही देखा है और अपने ही कार्यक्षेत्रों में सारा कुछ खर्च करने की कोशिश की। इसी तरह से नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ और एक ही हलके के 600-700 लड़के भर्ती कर डाले। आज हमें इस बात की खुशी है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार पूरे हरियाणा को एक ही आंख से देखती है, विकास के कार्यों में भी और उसी तरीके से नौकरियों में भी। फर्स्ट टाईम जे०बी०टी० के एडमिशन मैरिट पर हुये। पिछली सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीच्यूट्स की शक्ल और रूह ही बिगाड़ कर रख दी थी। ऐसे-ऐसे बच्चे जे०बी०टी० कोर्स में भर्ती कर दिये जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। मेरे गाँव में जे०बी०टी० का एक इंस्टीच्यूट है, हमने देखा है कि कैसे-कैसे लोग भर्ती किये गये हैं। कई बार ये बच्चे मुझे मिल जाते हैं तो कहते हैं अंकल हम तो बिल्कुल खाली पेपर देकर आये थे। वे बालक जिन्होंने आगे जाकर बच्चों को पढ़ाना है और स्टेट का भविष्य बनाना है इस प्रकार के बालकों से आप क्या उम्मीद करेंगे जो अपने पेपर खाली देकर आये थे। इस सरकार की यह बहुत बड़ी अचीवमैंट है कि इस बार सबऐडमिशन मैरिट पर हुये हैं और पूरे हरियाणा से भर्ती हुई है। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। मैंने तो हमेशा से इस हाउस में भी एक बात कही है और लोगों ने भी कही होगी कि पूर्ण हरियाणा को इस बात के बारे में बताना बहुत जरूरी है और हमने इस पर श्वेत-पत्र की भी मांग की है। हरियाणा बनने के बाद विकास के कार्यों में टोटल कण्ट्रीब्यूशन किन-किन पार्टस का स्टेट में कितना-कितना रहा है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसी तरह से नौकरियों के बारे में भी श्वेत-पत्र जारी होना चाहिये कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितने लड़के-लड़कियां भर्ती हुईं और वे कहां-कहां के थे। हरियाणा के लोग यह बात जानना चाहते हैं और मुझे आशा

[श्री निर्मल सिंह]

है कि सरकार द्वारा इस तरफ भी ध्यान दिया जायेगा। हमने यह बात कुरूक्षेत्र में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की हाजरी में कही थी जिसमें इन्होंने खुद शिरकत की थी और यह उस सभा के मुख्य अतिथि भी थे। मैं आशा करता हूँ कि इससे लोगों को जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मैं अपनी कांस्टीच्यूएंसी के बारे में 2-3 मिनट के लिये जिक्र करना चाहूँगा। मेरी कांस्टीच्यूएंसी बहुत बड़ी कांस्टीच्यूएंसी है और शायद हरियाणा की सबसे बड़ी कांस्टीच्यूएंसी है, जगाधरी रोड़, उसके बाद जी.टी. रोड़, उसके बाद हिसार रोड़ और पंजाब की डकाला और बन्नौर कांस्टीच्युएंसी, ऊधर पेहवा, शाहबाद, मुलाना और उसके बाद अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी होते हुये बनूड़ हलके से मिलती है। एक-एक गाँव से दूसरे गाँव तक 70 किलोमीटर का डिस्टैंस है और इसमें 165 गाँव हैं इसलिये इस हलके का विशेष ख्याल रखा जाये। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 50-50 लाख रुपये सभी विधायकों को देंगे लेकिन मेरी कांस्टीच्युएंसी में तो 50 लाख रुपये का पता भी नहीं चलेगा कि कहां खर्च हो गये। मुझे आशा है कि मेरी कांस्टीच्युएंसी का पूरा ख्याल रखा जायेगा। स्पीकर सर, इसी तरह से परिवहन मंत्री यहां पर बैठे हुये हैं मैं उनसे कहूँगा कि जो पुराने प्राइवेट रूट्स थे उनमें कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाये। इसके बारे में जब भी बात उठायी जाती है या कोर्ट में जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे नन्यौला का एक रूट था, अम्बाला से सीधे नन्यौला बस जाती थी वहां पर दो ही बसें हैं जो कि काफी नहीं हैं। लोगों को बसों की छतों पर भी सफर करना पड़ता है, उनसे मनमाना किराया भी बस ऑपरेटरों द्वारा वसूल किया जाता है और लोग बस ऑपरेटरों के नखरे भी बर्दाशत कर रहे हैं। स्पीकर साहब, इसी तरह से मैं हैल्थ मिनिस्टर जी से भी कहूँगा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में तीन गाँव हैं जिनकी आबादी करीब 50 हजार है। बोह, बबियाल और दलीपगढ़ पास-पास ही हैं और त्रिवेन की तरह जुड़े हुये हैं। यहां के लोगों को इलाज के लिये अम्बाला जाना पड़ता है। बोह गाँव ने अस्पताल खोलने के लिये जमीन देने की बात भी कही है हम वहां पर एक छोटा सा अस्पताल खोलने की मांग करते आये हैं। मुझे आशा है कि हमारी यह मांग जरूर पूरी की जाएगी। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि अम्बाला कैंट में एक ऐस्ट्रोटर्फ मंजूर हुआ था लेकिन पिछली सरकार की ज्यादती के कारण उसको शाहबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं यह मांग करता हूँ कि अम्बाला कैंट में भी ऐस्ट्रोटर्फ बनाया जाये। अम्बाला कैंट इसके लिये सभी नॉर्म्ज पूरे करता है और जब इस ऐस्ट्रोटर्फ को बदलने का फैसला लिया गया था उस वक्त इसके लिये गलोबल टैंडर भी हो चुका था। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने आज पूर्ण हरियाणा में बराबर पानी बांटकर दिखाया है और बहुत बड़ी नहर का निर्माण किया जा रहा है। मैं इनसे यह कहूंगा कि साउदर्न हरियाणा ही नहीं नॉर्दन हरियाणा भी है जो पानी के मामले में भी पीछे रहा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मात्र एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जिसकी कैपेसिटी 165 क्यूसिक है और आज पिछले सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें उन्होंने कभी भी 65 क्यूसिक से ज्यादा पानी लिफ्ट नहीं किया है। जब उनसे इसके बारे में कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी 165 क्यूसिक पानी लिफ्ट करने की है तो वे कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है क्योंकि यह खराब हो चुकी है और इसकी मुरम्मत होनी है। स्पीकर साहब, वहां पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मंजूर है मैं मंत्री

जी के नोटिस में भी लेकर आया हूँ। मन्सूरपुर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जिसकी कैपेसिटी मात्र 2700 क्यूसिक की है। अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ वर्क हो चुका है लेकिन पिछली सरकार ने पिछले पांच सालों से इसकी तरफ पलटकर नहीं देखा है। आज से 6 साल पहले इस स्कीम का अर्थ वर्क पूरा हो चुका था लेकिन बाद में सरकार ने इसको और मेरे हलके को काफी नजर अंदाज किया है। मुझे सरकार से आशा है कि मेरे हलके की तरफ पूरा ध्यान देगी। धन्यवाद।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, जिला फतेहाबाद की रतिया तहसील के पुलिस स्टेशन भूना के गाँव कुनाल में एक दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। (शोर)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इन्दौरा साहब ने एक विषय रेज किया है। रतिया तहसील के पुलिस स्टेशन भूना के गाँव कुनाल में एक दलित परिवार के बारे में उन्होंने प्वायंट रेज किया है।

वाक आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का नाम बोल्कर प्रकरण में उजागर हुआ है और जैसा कि इस बारे में हमारा स्टैंड रहा है तो उसी के मुताबिक हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। हम इनको सुनना नहीं चाहते इसलिये हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आऊट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप सुनिये। मंत्री जी आपका जवाब देने लग रहे हैं। अगर आप उनका जवाब सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर आप यहां पर किस लिये आये हैं? हाउस की एक डिगनिटी होती है।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

मंत्री द्वारा वक्तव्य (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक विषय रेज किया था। परन्तु उनको पूरे तथ्यों की कभी भी जानकारी नहीं होती है और हमेशा वे बगैर तथ्य जाने सदन का समय नष्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह मामला था। रतिया तहसील में पुलिस स्टेशन भूना के गाँव कुनाल में बिरसा सिंह और मिल्खा सिंह जो जरनैल सिंह के पुत्र हैं उनका हमारे दो दलित साथी बूटा सिंह वगैरा के साथ मकान को लेकर आपसी झगड़ा हुआ। सरकार को जैसे ही इस बात की खबर मिली तो मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एफ.आई. आर. नम्बर 19 डेटिड 15 जनवरी, 2006 पुलिस स्टेशन भूना, फतेहाबाद में अंडर सैक्शन 148, 149, 323, 506, 427, 448, 379 आई.पी.सी. और सैक्शन 25 आर्म्ज ऐक्ट में हमने दर्ज कर लिया है। स्पीकर साहब,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

उनके दो मकानों को क्षति पहुंचाई गई थी। इसलिये इस बात को देखते हुये मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार एक गारद जिसमें एक हैड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल हैं उनके घरों पर लगा दिये गये हैं। वहां पर जमीन को लेकर और उसकी मल्कियत को लेकर विवाद था। सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत दो प्लाट बूटा सिंह और उनके दो साथियों को आवंटित कर दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ डी.सी. फतेहाबाद ने 25 हजार रुपये की राशि अपने कोष से इन साथियों को भी दी है और खुद एस.पी. फतेहाबाद इस समय मौके पर हैं। वहां पर इस प्रकार का कोई जातिगत क्लेश नहीं है। वहां पर दो ग्रुप्स का गाँव के अंदर झगड़ा था। फिर भी पूरी स्थिति को देखते हुये यह कारगर कदम सरकार के द्वारा उठा लिये गये हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आयेगी तो उसके लिये मैं सदन को सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सचेत हैं, सजग हैं। जहां भी थोड़ी सी बात आयेगी मुख्यमंत्री जी इस पर पैनी नजर रखे हुये हैं हर बात का पूरे का पूरा इलाज किया जायेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर यही जानकारी रखना चाहता था। यह भूना का वाक्या है, रतिया का वाक्या नहीं है। जो सदन में डॉ० इन्दौरा जी ने कहा था वह पूरे तथ्यों के बगैर कहा था। पूरे तथ्यों के बगैर बोलना उनकी आदत बन चुकी है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब श्री बलवंत सिंह सढौरा बोलेंगे।

(इस समय माननीय सदस्य श्री बलवन्त सिंह सढौरा सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष : अगर सढौरा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं तो अब श्री राम कुमार गौतम जी बोलेंगे।

श्री रामकुमार गौतम (नारनौंद) : सम्मानित सदस्यगण और सभी सदन में हाजिर बहनो और भाइयो, मैं सभी को नव वर्ष के अवसर पर हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे एक साथी का नाम बोलने के लिये पुकारा है। अब वे सदन में आ गये हैं। क्या आप उनको बोलने का समय देंगे?

Mr. Speaker : I will provide the opportunity. (Intrruptions) Mr. Indora, after all you should maintain the dignity of the House. आपके 18 मिनट बनते थे और आप 44 मिनट बोले हैं। (विघ्न) 2-2 मिनट देने से कैसे काम चलेगा। (विघ्न) डॉक्टर साहब, अगर आप पिछले हाउस में होते तो आपको पता चलता कि किसको कितना समय बोलने के लिये मिलता था।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी गौतम जी बोल रहे हैं इसलिये इनको कुछ तो सदन में मर्यादा बनाये रखनी चाहिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाह रहा था कि क्या बलवन्त सिंह सढौरा जी को बोलने का समय मिलेगा?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं क्योंकि न तो आप डिप्टी लीडर हैं और न ही आप अपोजीशन के लीडर हैं? (विघ्न) सढौरा जी, खुद यहां बैठे हुये हैं वे खुद इस बारे में कह सकते हैं कि I am sitting here.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, अगर वे यहां बैठे हैं तो इनको बोलने का मौका दे दिया जाये।

Mr. Speaker : No, no, not at all. In what capacity you are saying ? The Hon'ble Member is sitting here. He himself can say to me that he is sitting. I am present in the House. (Interruptions) No, Dr. Sahib, please sit down. Please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों को बोलने की आप द्वारा पूरी आजादी दी गयी है।

श्री राम कुमार गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित सदस्यगण, बहनों और भाइयों जो हाजिर हैं मैं सभी को नये साल के अवसर पर बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सारी दुनिया में इस आने वाले नये साल में अमन रहे, शांति रहे, हमारा देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहे। हमारा हरियाणा प्रदेश देश में एक अग्रणी प्रान्त रहे। हरियाणा के सभी भाईयों को आने वाले समय में न्याय मिले, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो। सबको सबका हक मिले, किसी वर्ग के साथ ज्यादती न हो, सभी फलें फूलें। अध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को हमारे महामहिम गवर्नर के एड्रेस में सरकार की जो रोजी पिक्चर पेंट की गयी है मैं उसके बारे में कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले करप्शन के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। अभिभाषण में करप्शन के कंट्रोल की बात कही गयी है, नियंत्रण की बात कही गयी है। पिछली सरकार में करप्शन का गॉडफादर, डिस्क्रिमनेशन का, लूट का गॉडफादर एक पूर्व मुख्यमंत्री था। (शोर एवं विघ्न) मेरी बात तो सुनिये। (शोर एवं विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन बातों को मानते इन्दौरा साहब भी हैं लेकिन साथ ही साथ मुस्कराते भी हैं और हाँ भी भरते हैं।

श्री राम कुमार गौतम : मैं तो यह कहता हूँ कि करप्शन को दस महीने के कार्यकाल में हुड्डा साहब आप भी कंट्रोल नहीं कर सके हैं, करप्शन उसी तरह से है। थाने में करप्शन है, तहसील में करप्शन है, पटवारी के पास करप्शन है, सेल्स टैक्स ऑफिस में करप्शन है, डी.टी.ओ. के दफ्तर में करप्शन है। आपके आस-पास जो बैठते हैं वे भी करप्शन पर कंट्रोल नहीं कर पाये। अगर आप सही मायनों में हरियाणा की जनता को मैसेज देना चाहते हैं और करप्ट लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं तो आप उन ऑफिसर्ज और उन पॉलिटिशंज को आइडैंटिफाई कीजिये और उसके बाद एक्शन लेना शुरू कीजिये। तो आपको पता लगेगा कि एक हफ्ते में ही करप्शन होना बंद हो गया है। आप लिहाज मत कीजिये रोहतक का, मत लिहाज कीजिये कि

[श्री राम कुमार गौतम]

कोई आपकी बिरादरी का है, किसी एम०एल०ए० का रिश्तेदार है, किसी का साला है, जीजा है, आप यह लिहाज मत कीजिये। आप एक्शन लेना शुरू कीजिये तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि करप्शन कहां गया। जब तक आप हरियाणा के सबसे करप्ट आदमी जो इन विपक्षी साथियों का भाई है करप्शन का सरताज है। वह यहां हाजिर नहीं है जब तक उस पर हाथ नहीं डालेंगे, जब तक उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज वह उसी तरह घूम रहा है, वह दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है उसकी हर शहर में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं (शोर एवं विघ्न) आप मेरी बात को गौर से सुनिये। ओम प्रकाश चौटाला का आज भी पैराफर्नेलिया यूं का यूं आज आपके साथ है। आप गौर कीजिये, वही भू-माफिया, वही ऑफीसर्ज हैं आपने किसी को सबक नहीं सिखाया। हरियाणा प्रदेश की जनता को आपसे उम्मीद थी कि आप बनते ही एक महीने के अंदर ओम प्रकाश चौटाला को अंदर करके जितनी ज्यादतियां और बदमाशियां उसने की हैं अपने कार्यकाल में, उन सबका हिसाब लेंगे। अगर आप ऐसा करते तो आज उनकी ताकत नहीं होती। आज वे मुजारे कर रहे हैं, प्रौसेशन कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आये हैं, वे तो अपने मुकदमों का बचाव करते-करते धाराशायी हो जाते और ये उनके पक्ष में नहीं बोलते, केवल एक बात कहते कि हमारे को बचाओ, हमारे नेता को बचाओ। यह मैं दावे से कहता हूँ। इसके अलावा आपके पास ऑनैस्ट ऑफीसर्ज की कमी नहीं है, आपके पास बहुत ईमानदार ऑफीसर्ज हैं। यह नहीं होना चाहिये कि वह ऑफिसर फलां हलके का है, फलां तबके का है और आपका क्या लगता है। हमारे पास कितने ही ऑनैस्ट ऑफिसर भी हैं उसमें चाहे कामराज जी हों चाहे वी.एन.राव. जैसे आफिसर हैं। आपको जो ईमानदार और बढ़िया ऑफीसर्ज हैं। उनको रिवार्ड देना चाहिये और जो बेईमान ऑफीसर्ज हैं उनको आईडैंटिफाई करके सजा दीजिये। ऐसा अगर सरकार करती है तो हरियाणा में करप्शन का निशान नही रहेगा, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सदन के सभी सदस्यों के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जब ये मुख्यमंत्री जी बने थे उस समय इन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दि हाउस यह बात मानी थी कि पिछली सरकार के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जुल्म के शिकार 25 हजार इम्पलाइज बने थे। आपसे लोगों को बड़ी आशायें थीं कि आप ज्योंही मुख्यमंत्री पद की ओथ लेंगे तो उन कर्मचारियों के घरों में भी चूल्हे चसेंगे। पिछली सरकार ने इन कर्मचारियों पर बड़ा अन्याय किया है। मैं आपसे यह चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अब आप इस काम में देरी न करें, इसके बारे में कोई कमेटी की मीटिंग न करें बल्कि फटाफट आदेश जारी कर दें ताकि नये साल के उपलक्ष्य में उन कर्मचारियों के घरों में चूल्हे चसने लग जायें। तीसरी बात मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ। बिजली के बारे में बहुत बहस हो चुकी है इसलिये मैं बिजली के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं सदन की जानकारी के लिये केवल इतना बताना चाहता हूँ कि बिजली की बहुत भारी दुर्दशा है। हालांकि आपने जो बिजली के बिल न भरने के डिफाल्टर्ज लोग थे, उनका 1600 करोड़ रुपया माफ करने का काम करके बहुत बड़ी गलती की है। जबकि जो लोग बिजली के बिलों के रेगुलर पेईज थे उनको आपने कोई इन्सैंटीव नहीं दिया। उनको आपने कोई शाबाशी नहीं दी जो आपको देनी चाहिये थी। इसके अलावा ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन के लिये किसानों ने एक-एक साल से एक-एक लाख रुपये जमा

कर रखे हैं। एक साल के बाद उनके पास सरकार का मैसेज आता है कि ऐसा करो आप अपना सामान खुद खरीदकर ले आओ तो आपका कनैक्शन लग जायेगा। जब वे सामान खरीदकर ले आते हैं तो उनको कहा जाता है कि यह पैसा आपके बिलों में एडजस्ट करते रहेंगे। आज बिजली बोर्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है। सरकार इस समय बिजली बोर्ड को काबू करे वरना बिजली सरकार के काबू से बाहर चली गयी तो सरकार को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ेगी। जहां तक इरीगेशन की बात है। इस समय आप कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा के भाईयों को पानी मिल जाये, जिनको पहले पानी नहीं मिलता था। लेकिन यह सरकार एक मेहरबानी करे कि हमारे लोगों के साथ ज्यादती न करे। क्योंकि मेरे हलके के गाँवों बड़-छप्पर, बास, पुट्ठी, मौहल्ला के लोगों ने मुझे बताया कि पहले जो किला डेढ़ घण्टे में भरता था अब वह 6 घण्टे में भरता है। नहर की भोरी इतनी भीड़ी केवल 4 इंच की भोरी कर दी गयी है। मुख्यमंत्री जी, आप मेरी इस बात को नोट कर लें। इसका कारण भिवानी के लोगों को पानी देने का नहीं है। आप एस.वाई.एल. की लड़ाई इफैक्टिव तरीके से लड़ो तभी जाकर हरियाणा को एडीशनल पानी मिलेगा वरना आप जस्टीफाई नहीं कर सकेंगे। जहां तक फ्लड कंट्रोल की बात है इसके लिये सरकार मास्टर प्लान बनाने की बात कह रही है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी फ्लड कंट्रोल के बारे में मास्टर प्लान बनायें क्योंकि मेरे हलके के गाँव भखलाना, मोहल्ला, बास, बधौर और कवाना के गाँव फ्लड से बिल्कुल तबाह हो गये हैं और इसके लिये सरकार ने कोई कम्पनसेशन न देकर भी उन लोगों पर एक और जुल्म किया है। मेरे काबिल दोस्त चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने लेबर-लॉ के बारे में जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से उनके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ कि आज वे जो मिनिमम वेजिज 2360 रुपये की बात कर रहे हैं वह भी आज फैक्टरियों में लागू नहीं हैं। हमारे मजदूर भाई 1400-1500 रुपये प्रतिमाह की मार हर फैक्टरी में झेल रहे हैं और यही कारण है कि 85-90 प्रतिशत कर्मचारी बेचारे बहुत भूखे और गरीब हैं। यू.पी. और बिहार के लोग आकर यहां इम्पलायमेंट में लगते हैं। इस बारे में सरकार जल्द से जल्द एफैक्टिव स्टैप्स उठाये और इन फैक्टिरियों को काबू करें क्योंकि आज 2360 रुपये में कुछ नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, वाईंड अप कीजिए।

श्री राम कुमार गौतम : कांग्रेस के राज में गैस की कमी हो गयी है। पहले गैस खूब मिलती थी अब क्या बिजली पड़ गी। आज जबरदस्त गैस की मांग है और गैस ब्लैक में मिल रही है। पहले वाजपेयी जी की सरकार के समय में कपास का भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था और कांग्रेस के समय में 1500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलता था। इसी तरह से सरसों का रेट उस समय 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता था जबकि अब यह 1400 रुपये क्विंटल बिक ली है। सरकार भाव को थोड़ा कंट्रोल करे जो राजीव गांधी एजूकेशन सिटी बन रही है उसके लिये 2068 एकड़ जमीन अभी लेनी है। इसके बारे में मेरा थोड़ा सुझाव है कि कुण्डली दिल्ली के नजदीक है और वहां की एक-एक एकड़ जमीन 50-50 लाख या एक-एक करोड़ रुपये की है। मेहरबानी करके किसानों को पूरा कम्पनसेशन सरकार दे और कम्पनसेशन मार्किट रेट पर दे। नहीं तो वहां से 50 एकड़ दूर हमारे डाटा मसूदपुर में पंचायत की हजारों एकड़ जमीन

[श्री राम कुमार गौतम]

खाली पड़ी है वहां के लोग इस एजूकेशन सिटी के लिये जमीन फ्री दे देंगे और लोग खुश भी हो जायेंगे। अध्यक्ष महेदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहकर अपना स्थान लूंगा लेकिन बीच में एक छोटी सी बात और भी कहूँगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि आपने भय मुक्त प्रशासन की बात की थी लेकिन अभी तक भयमुक्त प्रशासन हुड्डा सरकार नहीं दे सकी, हालांकि सरकार ने कोशिश की। अभी भाई निर्मल सिंह जी जिक्र कर रहे थे ****

श्री अध्यक्ष : अभी रामकुमार गौतम जी जो निर्मल सिंह जी की बात कर रहे थे वह रिकॉर्ड न की जाये।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजीशन आज भी अच्छी नहीं है। इस समय लॉ एण्ड ऑर्डर की बहुत खतरनाक पोजीशन है। मैं चाहता हूँ कि सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर पर काबू करे। आज हालात बहुत खराब हैं, आने वाला साल जो है उसमें कम से कम गुड़गांव जैसे कांड और गोहाना जैसे कांड दोबारा न हों जहां दलित समाज को भागना पड़ा। एक और ऐसा कांड हुआ जिसका मैं आज जिक्र नहीं करना चाहता, इसका जिक्र मैं फिर कभी करूंगा। वह भी गोहाना का ही कांड है जिसमें सरकार को जलील होना पड़ा और धारायें बार-बार बदलनी पड़ीं धारा 307 को दो बार बदला गया। धारा 384 का नाम मैं नहीं लूंगा। मेहरबानी करके आगे के लिये ऐसा काम करें कि कम से कम बदमाशों के दिमाग में यह खौफ रहे कि अब अच्छा राज आ गया है और चौटाला का राज नहीं है, अच्छे लोगों का राज है।

Mr. Speaker : Gautam Ji, now please take your seat. अब श्री बचन सिंह आर्य जी बोलेंगे।

श्री बचन सिंह आर्य (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिये आपका धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, इस बारे में मेरे साथियों ने बड़े विस्तार से चर्चा की। यहां कानून और व्यवस्था का जिक्र चल रहा था इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार बनने से पहले प्रदेश में भय का वातावरण बना हुआ था। बदमाश, लुटेरे दुकानदारों और व्यापारियों का अपहरण किया करते थे। लोग मार्किट में सामान लेने जाते थे तो उन्हें अपनी कारों, मोटर साइकिलों की रखवाली के लिये अपने साथ दो आदमी ले जाने पड़ते थे। यह बात सारे हरियाणा के लोगों को पता है कि प्रदेश में ऐसे बुरे हालात थे। इस सरकार ने प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर कंट्रोल किया है इसके लिये मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ। जहां तक करप्शन की बात है तो इसको दूर करने के लिये भी सरकार प्रयास कर रही है मगर करप्शन समाज के अंदर हर वर्ग के अंदर कैंसर की तरह फैला हुआ है। करप्शन केवल अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में ही नहीं है बल्कि चारों तरफ करप्शन जड़ें जमाये हुये है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार ने करप्शन पर कंट्रोल करने के लिये प्रयास किया है और उसमें कुछ हद तक सरकार को सफलता भी मिली है लेकिन पूरी तरह से करप्शन

15.00 बजे

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

खत्म नहीं हुयी है। यह सही है कि हम बतौर विधायक जब हमारे सीनियर अधिकारियों से मिलते हैं तो वे हमारे से बड़े सम्मान से मिलते हैं और हमारी बातें भी मानते हैं। सभी जगह ईमानदार अधिकारी लगे हुये हैं लेकिन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर अभी करप्शन कंट्रोल नहीं हुआ है। सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये ताकि आम आदमियों की दिक्कतें दूर हो सकें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि के बारे में बात करना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि का भी जिक्र किया गया है कि बहुत उन्नत किस्म की कृषि किसानों से करवाई जायेगी ताकि उनका उत्पादन बढ़े। सरकार का यह प्रयास बहुत अच्छा है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त किसानों को गन्ने का भाव भी सरकार ने सबसे ज्यादा दिया है। इसके लिये चारों तरफ आम व्यक्ति सरकार की सराहना कर रहा है कि पहली बार किसानों को 135 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भाव दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी असंध में शूगर मिल खोलने की घोषणा करके आये हैं। इस बारे में वहां पर 30-40 हजार किसानों ने एक सभा की और उस सभा में सभी ने हाथ उठाकर निर्णय लिया है कि वे गन्ने की खेती अधिक करेंगे और लगने वाली उस शूगर मिल में गन्ने की कमी नहीं रहने देंगे। इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुर्रा नस्ल की भैंस का जिक्र भी किया गया है और पिछले बजट सैशन में भी वित्तमंत्री जी ने मुर्रा नस्ल की भैंस का जिक्र किया था। यह सही बात है कि हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे देश में मशहूर हैं। मुख्यमंत्री जी और सरकार ने मुर्रा नस्ल की भैंसों को बढ़ावा देने के लिये पैसे की व्यवस्था की है। मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगा और इस बात का मुझे बड़ा अफसोस भी है कि हरियाणा प्रांत वैदिक धर्मों के नाम से जाना जाता है और ऐसे प्रदेश में न तो बजट सैशन में और न ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं पर भी गऊ माता का जिक्र नहीं किया गया है। आप सभी को मालूम है कि चुनावों के अवसर पर या किसी दूसरे शुभ अवसर पर हम गाय को ही नमस्कार करके अपना कार्य शुभारम्भ करते हैं। यदि उस समय हमें गाय के दर्शन हो जाते हैं तो हम उसके सामने नतमस्तक होकर निकलते हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत वर्ष और हरियाणा प्रदेश की अपनी एक अलग ही संस्कृति है। यदि हमारे यहां गायें ऐसे ही दर-दर भटकती रहीं तो यह हमारे लिये बड़े अफसोस की बात है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि गायों के बारे में भी सोचा जाये, विचार किया जाये। यह ठीक है कि धार्मिक संस्थायें, आर्य समाज की संस्थायें और अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता गऊशालाओं की तरफ ध्यान देकर गऊ माताओं की दुर्दशा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से गायों की देखभाल के लिये कोई सबसिडी देने की बात नहीं की जा रही है और न ही उनकी नस्ल सुधारने के लिये कोई कदम उठाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, गाय देश की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई है और इसका असर देश की आर्थिक नीति पर भी पड़ता है। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह गायों की देखभाल के बारे में उचित कदम उठाये। मैं सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिये पूरे सदन की तरफ से बधाई देता हूँ कि उसने गऊ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी, मुख्यमंत्री जी और हम सभी वैदिक धर्म मानने वाले हैं। इसलिये मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले बजट सैशन में गऊ माता के बारे

[श्री बचन सिंह आर्य]

में जिक्र जरूर किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया और कहा गया है कि जगह-जगह पर हास्पिटल्ज में उपचार किये जा रहे हैं। हमारी बहन करतार देवी, स्वास्थ्य मंत्री हैं वे हर जगह पर इस बारे में प्रयास करती रहती हैं कि डाक्टर्ज की उपलब्धि हर हास्पिटल में हो। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वैदिक औषधालय हैं उनमें भी अंग्रेजी दवाईयां मरीजों को दी जा रही हैं। जिससे भारत की और हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति पर साईड इफैक्ट पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जो पश्चिम की दवाईयां हैं वे पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिये तो अनुकूल हो सकती हैं लेकिन वे दवाईयां यदि यहां दी जायेंगी तो उनसे एक रोग तो खत्म हो जायेगा लेकिन दूसरा रोग शुरू हो जाता है इसलिये मैं चाहता हूँ कि उन औषधालयों का नाम आयुर्वैदिक औषधालय है तो वहां पर अंग्रेजी दवाईयां नहीं दी जायें। वहां पर पूरी तरह से आयुर्वैदिक दवाईयां ही दी जायें। जैसे कि हमारी बहुत से वैदिक ऋषि मुनियों की जो खोज है उसे लोगों तक पहुंचाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्य साहब, आपको बोलते हुये 8-10 मिनट हो गये हैं इसलिये अब आप वाईड अप करें। एक मैम्बर के बांटे दो अढाई मिनट आये हैं लेकिन हम मैम्बर्ज को एडजस्ट कर रहे हैं। बोलने के लिये अभी मैम्बर्ज की बहुत सी पर्चियां पड़ी हुई हैं। अगर एक-एक मैम्बर इतनी देर बोलेगा तो काम कैसे चलेगा? प्लीज बचन जी। अब आप वाईड अप करें।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं जल्दी ही वाईड अप कर दूंगा। (विघ्न) मैं इस बात का जिक्र इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोग इसको चाहते हैं। इस देश के अन्दर कितना काम इस बात को लेकर हो रहा है। आचार्य बाबा रामदेव जी और दूसरे लोग भी योग और आयुर्वेदा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिये बहुत भारी काम कर रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि आयुर्वेदिक औषधियों को भी इसमें रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नहर की बात है, मेरे इलाके सफीदों में भी आंदा के पास नहर आएगी। यह बात अलग है कि कोई विरोध करने के लिये इसका विरोध करे और गलत विरोध करना भी हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड़ करना है। जैसे किसानों के लिये, मजदूरों के लिये सर छोटू राम को आज किसान और गाँव का देहात का छोटे से छोटा काम करने वाला मजदूर भी जब बात आती है तो उनको किसानों और मजदूरों का मसीहा कहता है। सरकारें आया करती हैं और चली जाया करती हैं तथा परिस्थितियां बदला करती हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा की सरकार जिस दिन इस नहर को पूरा कर देगी जैसे सर छोटू राम को आज तक किसानों और मजदूरों का मसीहा कहा जाता है वैसे ही मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा यदि इस नहर को पूरा कर जाते हैं तो आने वाली जैनरेशन इनको हरियाणा का भागीरथ कहेगी। आने वाले समय में चाहे किसी भी वर्ग अथवा किसी भी समाज का व्यक्ति हो बहुत बड़ा लाभ उसको इस नहर से होने जा रहा है, मैं इसके लिये सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आपने सुन लिया, आर्य साहब क्या कह रहे हैं। आप जिस नहर का विरोध कर रहे हैं उसी नहर के बन जाने की सूरत में मुख्यमंत्री जी को भागीरथ कहा जायेगा। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : गौतम जी ने एक बात सही कही थी कि पानी का इन्तजाम तो कहीं से करें। नहरें तो चाहे कितनी बनवा लें लेकिन पानी कहां से लायेंगे? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आर्य साहब, आप अपनी बात को कन्कलूड करें। इन्दौरा साहब, आप जिस नहर का विरोध कर रहे हैं उसी के लिये ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को उसके लिये भागीरथ माना जायेगा (विघ्न) आर्य साहब इंडिपैंडेंट एम०एल०ए० हैं जो यह बात कह रहे हैं। उसको आप सुनें। (विघ्न) इन्दौरा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) Please learn and listen, (Interruptions and noices) Indora Sahib, please take your seat. आर्य साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

श्री बचन सिंह आर्य : स्पीकर साहब, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि दूसरी बातों का उल्लेख इसमें हो चुका है। विशेष बात यह है कि जैसे 3-4 नगरों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी योजना लेकर आये हैं यह भी सत्य है और अगर कोई व्यक्ति इस पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहे तो वह उसके दिल की बात है। हरियाणा के अंदर आज इससे एक विशेष वातावरण बना हुआ है और वास्तव में हर व्यक्ति यह समझ रहा है कि दिल्ली प्रदेश की तरह हरियाणा बनने जा रहा है। हर किसान की जमीन के एक किल्ले की कीमत एक-डेढ़ लाख रुपये हुआ करती थी आज वह किसान महसूस करता है कि मार्किट में उसकी जमीन का रेट इस पॉलिसी के आने से कहीं पर 20 लाख, कहीं पर 25 लाख, कहीं पर 30-40 लाख रुपये हो गया है। किसान आज यह महसूस करता है कि हरियाणा में दिल्ली की तर्ज पर जमीन के रेट बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के सफीदों की कुछ सड़कों का जिक्र करना चाहूँगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय ही लूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह पिछड़ा हुआ और बैकवर्ड इलाका है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपकी जो सड़कें हैं उनके बारे में आप लिख कर भिजवा दें, वे पढ़ी हुई मान ली जायेंगी, अब आप बैठें।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये एक ही बात कहना चाहता हूँ और ऋग्वेद के एक मन्त्र का उल्लेख करना चाहता हूँ जो उन पर पूरी तरह से लागू होता है। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है कि शत्रु को दूर भगाना इतना कठिन नहीं है उसको कोई भी दूर भगा सकता है कमजोर व्यक्ति भी शत्रु को दूर भगा सकता है। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे मित्र बनाना। शत्रु को पराजित करने वाले निःसंदेह वीर है किन्तु वह व्यक्ति महावीर है जो शत्रु को अपना मित्र बना लेता है। शत्रु की शत्रुता तभी समाप्त हो जाती है जब उसे मित्र बना लिया जाता है। यह वास्तव में सत्य है, आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी में यह गुण है। स्पीकर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुकल (एस.सी. कलायत) : स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिये धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिये समय दिया। गवर्नर साहब के अभिभाषण में हमारी सरकार के दस महीनों की

[श्रीमती गीता भुकल]

उपलब्धियों को पूरी तरह से बयान किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी क्षेत्र या कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा जिससे विकास से कोई भी वर्ग वंचित रहा हो। जो भी घोषणायें हमारे घोषणा-पत्र में की गयी थीं उससे भी ज्यादा हमारी सरकार के दस महीनों के कार्यकाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हुये हैं। पिछली सरकार अपने आपको एक किसान हितैषी सरकार कहती थी। किसानों के नाम पर भी उन्होंने वोट बटोरे जरूर थे लेकिन मुझे आज भी वह दिन याद है कि जब किसानों की छातियों पर गोलियां चलायी गयी थी। उस समय हमारे कलायत हल्के के शिमला गाँव का राम स्वरूप भी शहीद हो गया था। उस समय जाम लग गये थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार की बागडोर संभालते ही अपनी पहली कलम से उन किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किये और हाल ही में उन किसानों को शहीदों का दर्जा देते हुये शहीद परिवारों के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी। मैं इसके लिये सरकार की बहुत आभारी हूँ क्योंकि इनमें हमारे क्षेत्र का एक आदमी राम स्वरूप भी था। ये सभी परिवार भी इसके लिये सरकार के आभारी रहेंगे। पिछली सरकार अपने आपको किसानों का हितैषी कहती थी लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कारण था कि कलायत पिछड़ा क्षेत्र रहा और किसानों के लिये हमारी बहुत सी नहरों का पानी दस-दस सालों तक टेल पर कभी नहीं पहुंचा और अब क्या कारण रहे या अब ऐसा क्या हो गया कि मात्र दस महीनों के अंदर-अंदर ही चाहे बाता माईनर हो, चाहे तुशाला माईनर हो, चाहे कैलरा माईनर हो या चाहे सिरसा पैरलल हो, हर टेल पर आज पानी पहुंचा है जिसके कारण आज हर किसान का चेहरा खिला है। इस तरह से हमारी सरकार की और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की उपलब्धियां हैं। सरकार ने जो गन्ने के रेट बढ़ाये हैं उससे गन्ने की उपज करने वाले एक-एक किसान के चेहरे खिले हैं। अगर प्राकृतिक आपदा के रूप में चाहे ओले पड़े हों या चाहे पाला पड़ा हो तो उसके लिये भी हमारी सरकार ने उसी समय मुआवजा देने की घोषणा की। इसलिये अगर किसानों की हितैषी सरकार है तो यह हमारी कांग्रेस पार्टी की माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चल रही सरकार है। इसी तरह से महिलाओं की यदि हम बात करें तो पिछली सरकारों की महिलाओं के नाम पर बहुत सी घोषणायें कागजों में ही रहीं। लेकिन उन्होंने किसी भी घोषणा को अमल में लाने के प्रयास नहीं किये। जब से हमारी सरकार ने बागडोर सम्भाली है तब से आपको भी मालूम ही है कि सैक्स रेशो भी चिंता का विषय है, लड़कियों की घटती हुई संख्या चिंता का विषय है इसलिये इस पर भी हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और इस बारे में बहुत सी घोषणायें की हैं। वर्ष 2006 को ईयर ऑफ गर्ल चाईल्ड डिक्लेयर करके इस बात को बताया गया है कि हमारी सरकार किस तरह से महिलाओं के लिये और विशेष तौर पर लड़कियों के लिये एवं उनकी घटती हुई संख्या के लिये चिंतित है। लाडली नाम की योजना की घोषणा की गयी। इसी तरह से प्रियदर्शनी योजना है। लाडली सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना शुरू की गयी है। इस योजना में कहा गया है कि जिसके यहां पर लड़की है उसको अब यह इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जब उसकी उम्र 60 साल की होगी तो उसको बुढ़ापा पैंशन मिलेगी। अब हमारी सरकार उसको 55 साल का होते ही बुढ़ापा पेंशन देगी। इसी तरह से सर्वोत्तम माता को पुरस्कार देने की भी घोषणा की गयी है।

इस तरह से हमारी सरकार ने न केवल महिलाओं के लिये घोषणा की बल्कि स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि किसानों के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। मैं हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि मैटरनिटी हट खोले जायेंगे। लड़कियों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। न केवल डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बल्कि ब्लॉक लैवल पर सी०एच०सी० एवं पी०एच०सी० लैवल पर भी हर गाँव में मैटरनिटी हट ज्यादातर जगहों पर खोली गयी हैं और न केवल वहां पर ए०एन०एम० की व्यवस्था की गयी है बल्कि आशा स्कीम के तहत वहां पर हैल्पर को भी नियुक्त किया गया है कि कोई भी माता बहन जो कि प्रैगनैंट है उसका रजिस्ट्रेशन करके एक दिन से लेकर 9 महीने तक उनके टीकाकरण से लेकर उनकी डिलवरी तक का ध्यान हमारी सरकार ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने रखा। यह जो नियुक्तियां हुई हैं उससे हर माता खुश है, बहन खुश है क्योंकि उनको रोजगार देने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है इसके लिये हमारी सरकार बहुत ज्यादा बधाई की पात्र है। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र की बात है, इकोनोमिक सैक्टर की बात है। दस स्पैशल इकोनोमिक जोन बना कर हमारी सरकार औद्योगिक क्रांति लेकर आयी है। इसके लिये न्यू लेबर पॉलिसी की घोषणा करके यह बताया गया है कि न केवल इकोनोमिक डिवैलपमैंट होगी बल्कि लेबर के साथ हो रहे अन्याय के प्रति भी हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। इम्प्लौयी और इम्प्लौयर के रिलेशन को पूरी तरह से मैंटेन करेंगे, इसके लिये सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा। अधिकारियों पर भी लगाम लगाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देती हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैडम अब आप वाईड अप करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : ठीक है सर। इसके साथ ही साथ मैं इकोनोमिक सैक्टर के साथ जुड़ा हुआ जैसे हमारा सामाजिक क्षेत्र है, के बारे में भी कहना चाहूँगी। जिस दर से इकोनोमिक तौर पर हमारी सरकार ने हरियाणा को देश की पृष्ठभूमि में लाने का प्रयास किया है उसी तरह से सोशल सैक्टर के लिये सलाह देना चाहूँगी कि जो बुढ़ापा पेंशन महिलाओं के लिये पेंशन और विधवा पेंशन या जो बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है इसके लिये भी सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिये। एक ऐसी नोडल ऐजेंसी होनी चाहिए जिससे हमारी माताओं और बहनों को दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें। हमें उनका दुःख मालूम है कि विधवा होने के बाद हाथ में विधवा पेंशन का फार्म लिए हुए वे हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हमें विधवा हुए दो साल हो गए हैं लेकिन हमें आज तक पेंशन नहीं मिली। इस समस्या के समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट लैवल पर या ब्लॉक लैवल पर नोडल एजेंसी का निर्माण किया जाये ताकि हमारी दुःखी बहनें या जिनको सरकार ये बैनीफिट देने जा रही हैं, उनको यह बैनीफिट मिल सके। इसी के साथ-साथ बिजली के बारे में जैसा कि सभी लोगों ने जिक्र किया है। मैं केवल यह कहना चाहूँगी कि मेरा कलायत क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन दस महीने के इस सरकार के कार्यकाल में अगर आप कलायत क्षेत्र की तस्वीर देखेंगे तो अचम्भा होगा कि वहां तरक्की के कार्य चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैडम अब आप वाईड अप करें।

श्रीमती गीता भुकल : स्पीकर सर, मैं अंत में केवल एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहां बिजली की कमी की वजह से कलायत में 132 के.वी. के सब-स्टेशन की मांग पुरानी रही है और 32 के.वी. की चुराड़ गाँव में मांग रही है। उसे पूरा किया जाये। मात्र केवल आधा मिनट का समय लेते हुये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से लैंड ऐक्वायर करके प्लाटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुडा के सैक्टरों में किया जा रहा है, उसमें जिस तरह से विडोज की, आर्मी पर्सनल्स की, एक्स सर्विसमैन की और एस०सीज०, बी०सीज० की जो रिजर्वेशन है, मैं चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस बारे में ध्यान दें। बहुत से प्राइवेट बिल्डर्स जो लैंड ऐक्वायर करके प्राइवेट प्लाट काट रहे हैं, उनमें उनकी पूरी तरह से रिजर्वेशन होनी चाहिये ताकि जो हमारी धारणा हर वर्ग का विकास करने की चल रही है, वह पूरी हो और जो लोग उजड़कर आये हैं, सरकार उनको बसाने का कार्य करे। इन शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया कि मैं गर्वनर साहब के एड्रेस पर विचार विमर्श कर सकूं, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने सत्तासीन होते ही जो इण्डस्ट्रीज के लिये हजारों करोड़ रुपये की योजना बनाई है मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा काम इण्डस्ट्री को अपग्रेड करने के लिये किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी सरकार ने आज तक किया होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अम्बाला छावनी बहुत लम्बे अर्से तक पूरे भारतवर्ष में साईंटिफिक इंस्ट्रूमैंटस के लिये एक बहुत बड़ा हब रहा है। यहां से साईंटिफिक इंस्ट्रूमैंट्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। पूरे संसार में साईंटिफिक एक्सपोर्ट अम्बाला छावनी से किये जाते थे परन्तु पिछले 10-12 सालों में कोई भी सरकारी मदद न होने की वजह से अम्बाला छावनी में जो साईंटिफिक इण्डस्ट्रीज थी, वे टोटली खत्म हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सबमिशन करना चाहता हूँ कि जो हरियाणा में इण्डस्ट्री लगायी जा रही हैं उनमें से साईंटिफिक इण्डस्ट्रीज अम्बाला छावनी में लगायी जाये ताकि वहां हजारों लोग जो इस काम में एक्सपर्ट हैं, उनकी भी कला इसमें काम आ सकें और साईंटिफिक इण्डस्ट्री में अम्बाला का नाम एक बार फिर आ सके तथा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान हरियाणा प्रदेश को दे सके। हाई कोर्ट को अलग करने बारे में भी सरकार ने विचार विमर्श किया है, एक फैसला किया है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वास्तविकता तो यह है कि पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के एक होने की वजह से हरियाणा के लोगों को और पंजाब के लोगों को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 400-400 केसिज कॉज लिस्ट में पाये जाते हैं और एक बेल एप्लीकेशन का नोटिस होने में तीन-तीन महीने लग जाते हैं। किसी केस को क्वैश कराने के लिए 3-3 महीने की डेट लगती है और किसी केस का डिसीजन होने में 10-10 साल लग जाते हैं। अलग हाई कोर्ट होने से जितनी इन्कनवीनियंस हरियाणा के लोगों को होती थी, वह खत्म हो जाएगी। मेरी इस बारे में एक सबमिशन है कि इस फैसले को एक साल के अन्दर-अन्दर लागू किया जाये ताकि हरियाणा के लोग जो कई सालों से सफर कर रहे थे उनकी परेशानी खत्म हो जाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिये विशेषकर स्वास्थ्य के लिये कई कार्य योजनायें बनायी

हैं। लेकिन इस बारे में मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 में अम्बाला कैन्ट में एक सिविल अस्पताल बनाने के लिये 8 करोड़ रुपये का एस्टिमेट्स बनाया गया था लेकिन वह एस्टीमेट्स आज तक पास नहीं हुआ है जिसका नतीजा यह है कि जो सिविल अस्पताल अम्बाला छावनी में है वह जर्जर हालत में है और वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और न ही कोई डॉक्टर है। इसके अलावा अम्बाला छावनी में जब कोई प्रोपर्टी खरीदनी या बेचनी होती है तो उसके लिये एन०ओ०सी० की कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, एन०ओ०सी० लेना पड़ता है जबकि ऐसा प्रोवीजन हरियाणा में किसी भी शहर में नहीं है। It is a case where the policy matter is to be adopted for removing this NOC condition. इस एन.ओ.सी. को लेने के लिये एक साल से ज्यादा समय लग जाता है और न जाने कितने बड़े माध्यम पर करप्शन पैदा होती है। यदि किसी परिवार में माँ-बाप बीमार हैं और वह अपनी प्रोपर्टी बेचना चाहते हैं तो वह अपनी प्रोपर्टी बेच नहीं सकते। इससे लोगों को एक परेशानी यह होती है कि किसी को अपनी लड़की की शादी करनी होती है तो उस समय वह अपनी प्रोपर्टी बेच नहीं सकता और अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। इसलिये मेरी आपसे सबमिशन है कि इस एन०ओ०सी० की कन्डीशन को तुरन्त खत्म किया जाये। पूरे हरियाणा में अम्बाला छावनी एक ऐसी कांस्टीच्यूएंसी है जहां 30 प्रतिशत पापुलेशन आर्मी के अण्डर है और 30 प्रतिशत वोटर सिविल के हैं And they are governed by the army administration. मुझे बताते हुये बड़ा दुःख होता है कि आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन आम आदमी को एक सलेव की तरह ट्रीट करता है। जिस प्रकार से आजादी से पहले हिन्दुस्तानियों के साथ अंग्रेजों द्वारा सलूक किया जाता था वैसा ही सलूक आज हमारे यहां पर किया जा रहा है। सुबह एक घण्टा और शाम को एक घण्टा उन सड़कों पर सिविलियन आदमी को नहीं जाने दिया जाता जिन सड़कों पर आर्मी के ऑफिसर सैर कर रहे होते हैं। सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से जितना पैसा अम्बाला छावनी के सिविल एरिया की डिवलैपमैंट के लिये आता है, उस पैसे को आर्मी वाले खर्च नहीं करते, इस वजह से सिविल आदमियों को बिजली पानी और आम सुविधायें नहीं मिलती। इसलिये इसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया आपका धन्यवाद।

डॉ० सीता राम (एस.सी., डबवाली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 13 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन के अन्दर अपना अभिभाषण पढ़ा है। यह अभिभाषण सरकार की बीते हुये समय की सारी उपलब्धियों के बारे में बताता है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता के लिये यह सरकार क्या काम करने जा रही है, क्या योजनायें बनाई गई हैं। उनके बारे में यह अभिभाषण दर्शाता है लेकिन जब मैंने अब के गवर्नर महोदय के अभिभाषण को और पिछले गवर्नर महोदय के अभिभाषण को पढ़ा तो जो घोषणायें पिछले अभिभाषण में की गई थीं उसी को तरोड़ मरोड़ कर के इस सदन में पेश किया गया है। वे सभी घोषणायें घोषणायें बनकर रह गई थीं। और आज भी इस नये अभिभाषण में जो घोषणायें की गई हैं वे भी सिर्फ घोषणायें बनी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत भारी बहुमत हासिल करके सरकार बनाई है। इस सरकार से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
को यह जानकारी होनी चाहिये कि सदन में किस प्रकार बात करनी है। ये पीछे से स्पोर्ट मांग रहे हैं यह ठीक है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें मालूम नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था.....(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please take your seat. (Iterruptions) बगैर परमिशन के आप कैसे खड़े हो after all there are certain rules and regulations to conduct the House.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। मैं कह रहा था कि लोगों की उम्मीदें इस सरकार ने तोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी गलत प्रचार करने में माहिर है। जिसका परिणाम हमारी सरकार को उस समय भुगतना पड़ा। क्यों भुगतना पड़ा क्योंकि इन्होंने लोगों के अंदर जा जाकर प्रचार किया है कि बड़ा भय और बड़ा भ्रष्टाचार है लेकिन आज जिस भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सरकार बात करती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार झूठ की रेल के लिए मशहूर रही है। (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जिस भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात ये कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आज अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अधिकारी भयमुक्त हो चुके हैं, प्रदेश की जनता भयग्रस्त है। लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटकर आते हैं और जब तक अधिकारियों की जेबें गरम नहीं होती तब तक लोगों के काम नहीं होते और ये कहते हैं कि हमने भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे दिया है। भ्रष्टाचार में कैबिनेट के मंत्री तक शामिल हैं। बहुत बड़े तेल घोटाले में शामिल हैं और ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे दिया है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाईंट ऑफ ऑर्डर। क्योंकि इन्होंने मंत्रियों का नाम लिया है इसलिये मैं कहना चाहता हूँ। वैसे तो ये मेरे छोटे भाई हैं मुझे इनके बारे में नहीं कहना चाहिये। लेकिन उस सी.डी. में ये भी साथ बैठे हैं और नंगी लड़कियों का नाच देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये और डॉ० इन्दौरा दोनों छोटे भाई हैं इनके बारे कहना नहीं चाहिये। उस सी.डी. में इनके नेता के पुत्र नजर आते हैं, उसमें ये भी उनके साथ बैठे नजर आते हैं। (शोर एवं व्यवधान) जो कुख्यात बदमाश थे डिम्पी जो रूंगटा किडनैपिंग केस में है, उसके साथ-साथ जो जयपुर बलात्कार केस में इन्वाल्वड है, वे दोनों उस सी.डी. में इन भाई साहब के साथ बैठे हुये हैं जो लड़कियों का नाच देख रहे हैं। वहां डॉ० इन्दौरा भी हैं, वहां अजय चौटाला भी हैं, वहां अभय चौटाला भी है और वहां डॉ० सीताराम भी हैं, ये इनका खुद का कंडक्ट रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये पूरे प्रदेश को वह सी.डी. दिखायें, हमें कोई परवाह नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं वह सी०डी० आपको भी दे दूंगा। वह सी.डी. पत्रकार साथियों के पास भी है और मैं इस को यहां सदन के पटल पर भी रख दूंगा। इनका बड़ा अशोभनीय कंडक्ट रहा है। लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में इनका क्या कंडक्ट रहा है यह सबको मालूम है। अध्यक्ष महोदय, छाज तो बोले बोले छलनी भी बोले। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम अपने चाल, चेहरे और चरित्र पर जरूर नजर डालें कि ये और इनके नेता क्या करते थे? मैं अकेला इनके नेता और उनके पुत्रों के लिये काफी हूँ। मैंने इनके नेता को तीन-तीन बार रगड़ा लगाया है और एक बार तो ऐसा रगड़ा लगाया है कि दोबारा विधान सभा में वापिस नहीं आया। इसलिये इनकी पूरी पार्टी के लिये, इनके नेता के लिये और उनके दोनों बेटों के लिये वैसे तो हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत सदस्य हैं लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ। मैंने इनके नेता को तीन बार हराया है और अगली बार फिर हरा दूंगा। स्पीकर सर, मैं चुनौती देता हूँ इनके नेता को ये जाकर बता दें कि इनके नेता रोड़ी विधान सभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दें और दोबारा से चुनाव लड़े मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। वे जीत कर दिखायें तब हम इनकी लोकप्रियता को मानेंगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, वैसे भी इनके नेता को इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि वे अपने विधान सभा क्षेत्र की सदन में नुमाइंदगी करने आते ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इनकी सारी पार्टी के लिये मैं अकेला काफी हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह सब पाखण्ड है, दिखावा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इनके नेता में अपने क्षेत्र रोड़ी विधान सभा की नुमाइंदगी करने की क्षमता तो है नहीं। (शोर एवं व्यवधान) वे यहां पर एक साल से नहीं आये हैं और ये सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय,* * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, डॉक्टर साहब हमारे छोटे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि इनके परिवार के लोगों को मालूम हो कि ये अजय और अभय चौटाला के साथ मिलकर क्या-क्या करते थे ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय,* * *

श्री अध्यक्ष : ये मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। डॉक्टर साहब, प्लीज, आप अपनी सीट पर बैठें। यदि आपने अपने हल्के से सम्बन्धित कोई बात कहनी है तो कहें वरना आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आपको बोलते हुये 9 मिनट हो गये हैं और आपकी पार्टी के लिये टोटल 44 मिनट का समय है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम: स्पीकर सर, इनकी सरकार में आई.जी. रैंक के अधिकारी छोटे कर्मचारियों की परमोशन के लिये रिश्वत लेते पकड़े गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इनको इस बात के लिये सरकार की तारीफ करनी चाहिये कि सरकार ने ऐसे अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें मुख्यमंत्री जी का

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

शुक्रिया अदा करना चाहिये कि कोई अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, मुख्यमंत्री जी सबको एक नजर से देखते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा प्रशासन दिया है जो सबको एक नजर से देखता है चाहे कोई छोटा है या बड़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम: स्पीकर सर, आज प्रदेश में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। मुख्यमंत्री जी लोगों को कहते हैं कि रात के समय में गाँवों में केवल आधे घण्टे बिजली जाया करेगी लेकिन बात बिल्कुल उल्ट है। इस सरकार के समय गाँवों में केवल आधा घण्टा बिजली ही रात को आती है और आज ये हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, यदि आपके हल्के की कोई समस्या है तो आप बतायें वरना आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने क्या किया। पानीपत थर्मल प्लांट की दूसरी यूनिट आठ महीने में हमारी सरकार ने पूरी करवाई। (शोर एवं व्यवधान)

राजस्व मंत्री (अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, इन्होंने तो उसे खराब कर दिया। इन्होंने कमीशन खाकर खराब कोयला खरीद लिया और उन यूनिट्स में डाल दिया जिसके कारण वे खराब हो गयी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, प्लीज आप बैठें। अब प्रो० छत्तरपाल सिंह जी बोलेंगे।

प्रो० छत्तरपाल सिंह (धिराय) : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बिठाइये ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, आप अपनी सीट पर बैठें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा इस अभिभाषण का विरोध करता हूँ।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, थैंक्स, आपने मुझे गवर्नर के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। दो दिन से इस अभिभाषण पर बहस चल रही है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी पदासीन हुये)** चेयरमैन सर, अभी तक सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर बड़ी सन्तोषजनक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और विपक्ष के साथी जिन चीजों को लेकर यहां भाषण कर रहे हैं उसमें सरकार का विरोध करने की बातें आ रही हैं। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री जब अच्छी और साफ-सुथरी नीयत के साथ काम करने की इच्छा रखे और करना चाहेगा तो हो सकता है कि उसमें पाँच दस परसेंट सुधार होने की गुंजाईश हो, उसके लिये ओपोजिशन के साथियों को अपने सुझाव रखने चाहियें ताकि मुख्यमंत्री और सरकार के नुमायंदे उन सुझावों के ऊपर गहराई

के साथ सोच कर कोई कार्यवाही कर सकें, कोई कदम उठा सकें। चेयरमैन सर, तुलनात्मक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने एक मिरैक्ल किया है, 8-10 महीने के अन्दर जो पिछले 5-6 साल से अपराध के बीज बोये गए थे, उस फसल को काटा गया है। चेयरमैन सर, 5-6 साल के नासूर को ठीक करने में बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। 5-6 साल तक इन लोगों ने हरियाणा की जनता को, जवानों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को, व्यापारियों और जनता को अपराध की तरफ धकेला हो, उनकी आदतों को बिगाड़ने का काम किया हो, चेयरमैन सर, उसको इतनी जल्दी ठीक कर पाना भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जैसे कम्पिटैंट आदमी की सोच का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने अपने विधायकों की मीटिंग में यह कहने की हिम्मत की कि आप सभी लोग सहयोग और साथ दें। हमारी पार्टी का मैनिफैस्टो है अमन, चैन और शांति का, एक प्रांत हमने बनाना है। यह कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, कमिटमैंट रही है, हमें अपने प्रान्त को विकास की तरफ लेकर जाना है और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा का अच्छी सोच रखने वाला विपक्ष का व्यक्ति भी आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की इस नीति को समर्थन देना चाहता है क्योंकि जब वह हरियाणा में निकलते हैं तो सुख की सांस मिलती है। देहात के अंदर बैठे हुये किसान, व्यापारी, शहर के अंदर जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी बहुत जल्दी यह कहने के लिये मजबूर हुए हैं कि प्रदेश में अमन, चैन और शांति इस सरकार ने दी है। चेयरमैन सर, मैं एक और बात मैरिट के ऊपर कहना चाहता हूँ जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। राजनीतिक नेताओं की एक अपेक्षा हुआ करती है कि जो पिछला इतिहास है और हमने मैजोरिटी ऑफ नेताओं में देखा है कि कोई मुद्दा बने, कोई माहौल बने, लोग कोई बहुत बड़ी मांग करें और फिर उसका क्रेडिट लेने के लिये घोषणा करें और उस घोषणा का क्रेडिट नेता को मिले। चेयरमैन सर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसने किसी आन्दोलन अथवा किसी डिमाण्ड को डिवैल्प करने की या कोई माहौल बनाने की तरफ कभी नहीं सोचा बल्कि जो बात जेहन के अन्दर उपयुक्त लगी या अपने कुछ साथियों ने बता दी अन्यथा उनके सामने आई; उन्होंने इस बात को करेज किया कि मुझे उसका क्रेडिट मिले या न मिले लेकिन यह बात जायज है इसलिये यह बात लागू होनी चाहिये। चेयरमैन सर, पिछली अनेक घोषणायें उनकी नीयत का, उनकी सोच का अंदाजा कर रही है। आज हमें फख्र होना चाहिये, आज हमें गर्व होना चाहिये कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा पर लगे हुये इन नेताओं के कलंक धोने का काम किया है और बड़ी हिम्मत के साथ कुछ एक फैसले लिये हैं। मीन मेख निकालने के लिये या विरोध करने के लिये बहुत सारी बातों को खोदा जा सकता है, कहा जा सकता है लेकिन आज उनकी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आज उनको पोजेटिव देखने की आवश्यकता है। भाई निर्मल सिंह जी ने जिस बात का जिक्र किया वह एक मुद्दे की तरह हरियाणा के अंदर रही और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने उसको एक कमिटमैंट के साथ लिया है। इन्होंने डिस्क्रिमीनेशन को खत्म करने के लिये एक आन्दोलन के रूप में काम किया है इसलिये इस बात के लिये इनकी तारीफ की जानी चाहिये। चेयरमैन सर, मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी पार्टी के हैं। मैं यह बात इसलिये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनकी पार्टी का हूँ बल्कि मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूँ कि काम करने वाले व्यक्ति को अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे या उसके पक्ष में दो बातें नहीं कहेंगे तो

[प्रो० छतरपाल सिंह]

फिर ठीक काम करने वाले को एनक्रजमैंट कहां से मिलेगी? रिवार्ड और पुनिशमैंट दो ही तो आधार हैं। जब हम किसी बात को किसी दिशा में ले जाने के लिये जुडिशियस तरीके से काम करने के लिये लेकर चलते हैं तो इस बात की और ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। चेयरमैन सर, इस डिस्क्रिमीनेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है। हरियाणा के अंदर 80 प्रतिशत पोपुलेशन देहात में रहती है और वह कृषि पर ही आधारित है। हमारी रोजी रोटी खेती पर निर्भर करती है लेकिन सिंचाई के बिना कोई भी किसान हमेशा हताश ही रहता है। चेयरमैन सर, मैं जिला हिसार से ताल्लुक रखता हूं जहां से चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सिरसा जिला भी उसी हिसार का एक हिस्सा रहा है जहां से चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हमारा अपना जमाना था तो उस वक्त ही उस एरिया में किसानों को पानी देखने को मिला था लेकिन बाद में उन जिलों के अंदर 42 दिनों में केवल एक हफ्ते ही किसानों को पानी मिलता था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह पानी खिकता कहां पर था, वह पानी जाता कहां पर था? चेयरमैन सर, यह बहुत बड़ी सोच का विषय है, बहुत बड़ी इन्वैस्टिगेशन का विषय है। चेयरमैन सर, शुरू-शुरू में हमें अपने जिले में थोड़ी दिक्कत जरूर रही लेकिन मुख्यमंत्री जी और इरीगेशन मिनिस्टर के प्रभावी कदमों की वजह से, साफ नीयत की वजह से जिला हिसार के अंदर चाहे आदमपुर कांस्टीच्युएंसी हो, चाहे घिराए कांस्टीच्युएंसी हो, चाहे बरवाला कांस्टीच्युएंसी हो या चाहे भट्टू कांस्टीच्युएंसी के विलेजिज हों, उनकी नहरों की हर छोर पर पानी गया है। महीने के अंदर दो-दो हफ्ते पानी गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज हरियाणा के अनेक हिस्सों के अंदर पूरा पानी भेजने का काम किया गया है, किसान के खेत को और किसान के घर को खुशहाल करने का काम किया गया है।

श्री सभापति : प्रोफेसर साहब, अब आप वाईंड अप करें।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : सर, शुरूआत से पहले वाईंड अप! चेयरमैन सर, काम की बातें तो सुननी चाहियें।

श्री सभापति : प्रोफेसर साहब, सबको बोलने का टाईम मिलना चाहिये। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : शुक्रिया चेयरमैन सर, नहरों की सफाई भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा है। अभी भी हमारे अधिकारी लगे हुये हैं और वे बहुत ही अच्छी गति से काम कर रहे हैं। चेयरमैन सर, मैंने पहले इस बारे में एक सुझाव दिया था कि इंटरनल क्लीयरैन्स के साथ-साथ इनकी बाहर की सफाई भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक आप इरीगेशन चैनल्ज को, रीवर्ज को अंदर-बाहर दोनों जगहों से साफ नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। थैप्ट को आप रोक सकते हैं, पानी के वनत्व को आप बढ़ा सकते हैं और पानी को पहुंचा सकते हैं लेकिन इस बारे में फारेस्ट डिपार्टमैंट की जो वायलेशन है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से यह बात नोट कर लें और इस बात की इंक्वायरी भी की जानी चाहिये कि जो अफारेस्टेशन के लिये ईयर मार्क एरिया है जिसको इरिगेशन डिपार्टमैंट द्वारा छोड़ा गया है वहीं पर पेड़ों को लगाया जाये। चेयरमैन सर, नहरों की पटरियों पर पेड़ लगे हुये हैं जिससे रिसाव और

कटाव दोनों ही नोटिस में आये हैं और सीपेज का भी यही बहुत बड़ा कारण बनते हैं। चेयरमैन सर, आप भी इस बात की ताईद करेंगे। हरियाणा में किसानों की खेतों की खालों की रिपेयर के लिए बजट तकरीबन दस करोड़ रुपये रखा गया था। इतने पैसों से इन खालों की रिपेयर होनी है। पिछली सरकारों ने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया है। चेयरमैन सर, जब तक किसान के खेतों के खाले ठीक नहीं होते तब तक उसके खेत के अंदर पहुंचने वाले पानी की मात्रा में बहुत भारी कमी आती रहेगी, इरीगेशन के लेवल में कमी आती रहेगी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से विशेष तौर से कहूँगा कि इरीगेशन मिनिस्टर को बुलाकर आप इस पैसे को बढ़ाने का काम करें। चेयरमैन सर, एनवायरनमैंट के अंदर भी उन्होंने काफी सुधार किया गया है और लेबर पोलिसी भी सरकार द्वारा बनाई गई है। चेयरमैन सर, मैंने हिसार के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को देखा है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की वर्किंग में बड़ा इजाफा हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों के रवैये को देखकर काम करना शुरू किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सरकार के माध्यम से देहात के अंदर जो अव्यवस्थायें और व्यवस्थायें हैं उसमें रूरल डिवैलपमैंट विशेष तौर से हैल्थ डिपार्टमैंट, एजूकेशन डिपार्टमैंट का जो रोल है इसको हमें थोड़ा सा चैक करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री इस बात पर विशेष तवज्जो देंगे, ऐसी उम्मीद है। मैं कहना चाहूँगा कि आप रूरल डिवैलपमैंट के अंदर कितना ही पैसा दे दें लेकिन जब तक इंजीनियरिंग स्किल ठीक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक किसी सरपंच के कहने से, किसी पार्टी के कहने पर, किसी पोलिटीशियन के कहने पर गली को कहीं से ऊँचा बना दिया जाता है कहीं नीचा बना दिया जाता है। एक गली, एक गाँव को ठीक करने के लिये चाहे कितना भी पैसा दिया गया हो लेकिन अव्यवस्था आज वहीं की वहीं है। आज इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका डिवैलपमैंट डिपार्टमैंट जितना है डी.डी.ओ. है, डायरैक्टर है उसको थोड़ा चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक्सीयन, एस.डी.ओज और जे०ई०ज० सुनिश्चित करें कि सरकार का 10 रुपया भी यदि किसी गली के अंदर लगता है तो उसकी यूटीलिटी पूरी हो, उसको उखाड़कर दोबारा बनाने की आवश्यकता न हो। जिन्होंने गलतियां की हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिये।

श्री सभापति : आपको सात मिनट का समय दिया गया था जबकि आपको बोलते हुये 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया है। आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है आप दो मिनट में अपनी बात कह दें।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : ठीक है सर, मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि देहात के अंदर जो डॉक्टरों की और अदर स्टाफ की हाजिरी है उसमें सुधार के लिये किस प्रकार की मोटीवेशन दी जानी है इस बात की आज आवश्यकता है। देहात के अंदर नैगलीजैंट हाजिरी रहती है और उनका व्यवहार भी बहुत ज्यादा सराहनीय नहीं है। हैल्थ व्यवस्था को मैंटेन करने के लिये थोड़ी सी सख्ती की आवश्यकता है। दूसरे जो मुख्यमंत्री जी ने एजूकेशन फील्ड को इस्टैब्लिश करने की बात कही है। मैं शिक्षा मंत्री जी और चीफ मिनिस्टर साहब का विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस दिशा में हमारे स्कूल्स के अंदर जो मास्टर हैं वे हमारे पोलिटिकल साथी हो सकते हैं हमारे गाँव के परिवार के लोग हो सकते हैं लेकिन उनको भी बहुत

[प्रो० छतरपाल सिंह]

जागृति देने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा वर्क कल्चर डिवैल्प करने की आवश्यकता है क्योंकि देहात के स्कूलों का जो स्टैण्डर्ड है जो व्यवस्था है वह निश्चित तौर से बहुत दुखद है उसको हमें निश्चित तौर से ठीक करने में समय लगता है। बहुत बड़े-बड़े नासूर आपकी सरकार ने ठीक किये हैं। अब इस दिशा के अन्दर हमारा ध्यान इसलिये जाता है क्योंकि हम सुरक्षित हैं, शांत हैं। विकास की दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारा बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान जरूर जाता है। उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पर विशेष गौर करते हुये इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे।

श्री सभापति : प्रो० साहब अब आप बैठ जायें। आपका समय समाप्त हो गया है।

प्रो० छतरपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं दो लाइनों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भाई निर्मल सिंह जी ने जो जिक्र किया है। मेरी विधान कांस्टीच्यूएंसी है। 1977 का जो डीलिमिटेशन था उस वक्त की यह बनाई हुई है और उसमें तकरीबन ऐसे गाँव थे जो कि हमारी पार्टी के विरोधी माने जाते थे। बड़ी ही उबड़ खाबड़ कांस्टीच्यूएंसी थी। उस कांस्टीच्यूएंसी को ठीक कराने के लिए जो नीति नीयत का हिसाब है, उसे लाइन पर लेकर आए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां उन गाँवों के लोग वोट तो जमाने से उन निकम्मी पार्टियों को देते आ रहे थे। हमें वहां से एक बार 1991-96 के बीच मौका मिला था तो हमने काफी रोड्स बनाएं लेकिन उनकी रिपेयर उसके बाद से आज तक नहीं हुई है। बहुत बुरा हाल है। कुछ अस्पताल बनाएं हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में अपने दफ्तर के माध्यम से सारी चीजें आएंगी लेकिन मैं भी गुजारिश करता हूँ कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पर रोड्स की रिपेयर की आवश्यकता है। वहां कई रास्ते अभी भी कच्चे हैं उनको पक्का करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : यह जनरल मैटर है सारे प्रदेश में रोड्स का काम बहुत बढ़िया होने लग रहा है।

प्रो० छतरपाल सिंह : जिस इंटेशन से सरकार लगी हुई है उससे दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। ऐसा मुझे विश्वास है। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ए.सी. चौधरी (फरीदाबाद) : चेयरमैन साहब, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। किसी व्यक्ति या सरकार का विजिन उसकी प्लानिंग से चलता है और आज हमारी सरकार का विजिन राज्यपाल महोदय द्वारा 13 जनवरी 2006 को सदन में पढ़े गये अभिभाषण में एक-एक आईटम के बारे में सभी प्लानिंग के अनुसार विवरण दिया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। जहां मैं उस अभिभाषण की प्रशंसा करते हुए समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वहीं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सरकार के नोटिस में लाना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। चेयरमैन साहब, किसान के भविष्य के लिए और किसान के दुःख का अन्दाजा लगाते हुए जहां सरकार ने उनके लिए कई प्रोग्राम बनाये हैं और गन्ने जैसी फसल का देश में सबसे ज्यादा रेट देकर किसानों को एक नई रोशनी दी है

वहीं मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछली सरकार के समय में जिस तरीके से किसानों को जलील किया गया और किसानों की आड़ में अपने घर भरे गए तो वे बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उसका खुलासा मैं यूं करूंगा कि पिछली सरकार के समय में गेहूं का रेट बढ़ाने के बाद भी हरियाणा का किसान अपनी उपज को लेकर रोता रहा उसका एक दाना भी नहीं उठाया गया और इसकी बजाए उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ से उचैन्दी अनाज आया और वह सारा पैसा कुछ स्वार्थी लोगों ने सत्ता में रहकर कमाया। अब ऐसा न हो कि यही असली किसान के साथ कोई नये रूप में ठगी कर ले, इसके लिए चौकसी की जरूरत है। इसके साथ ही मैं आज की प्रोग्रैसिव सरकार से यह अपेक्षा करूंगा कि वक्त के साथ-साथ किसानों को जागरुक करने के लिए एरियावाईज क्रोप को आईडैंटिफाई करके उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि किसान को उसकी खून-पसीने की कमाई पूरी तरह से मिल सके। सरकार ने जो हुड्डा और बाकी एजेन्सियों द्वारा जमीन ऐक्वायर की है उसकी मिनिमम प्राईस डिक्लेयर करके किसानों के लिए बड़ी राहत का काम किया है इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ। एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहूँगा कि सिर्फ आपका सौहार्द, आपकी समझ किसान के भविष्य को तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसके बीच में आने वाले अवरोधक सरकार दूर नहीं कर पायेगी। इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कई गाँवों में जमीनें ऐक्वायर हुई हैं लेकिन इन्कम टैक्स वाले नये-नये टैक्स की आड़ में उन किसानों को पैसा नहीं दे रहे हैं जिससे किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। किसानों के एकाउन्ट्स सीज कर दिए गये हैं। मैं अपने हल्के के गाँव झाड़जेतली की मिसाल देना चाहूँगा जहां भारत सरकार ने किसानों का सारा पैसा यह कहकर सीज कर लिया है कि तुम्हारा इन्कमटैक्स काटा जायेगा और उसका नतीजा यह निकला कि जितना जमीन का पैसा उन किसानों को मिला उससे ज्यादा लायबलिटी उस पैसे को रिलीव करवाने की बन गई है। इसलिए सरकार को किसानों के दर्द को समझते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। कई मौके ऐसे आते हैं कि जब फसल बेचने के लिए किसान मण्डी में आता है तो उसको यह कहकर कि बारदाना नहीं है परेशान किया जाता है, बारदाने की आड़ में किसान का अनाज मण्डियों में पड़ा खराब हो जाता है और उसका नतीजा यह निकलता है कि वह किसान आहें भर कर रह जाता है। इसके लिए सरकार को अभी से ही गेहूँ की फसल के लिए कोई तरीका कर दिया जाए ताकि सरकार की अच्छी सोच का पूरा फायदा मिल सके। चेयरमैन साहब, हम भारतीय लोग देवी के उपासक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कुछ अनसक्रुप्लस लोग हैं जो अपने डॉक्टरी पेशे को बदनाम कर रहे हैं, जो अपने नर्सिंग होम की आड़ में भ्रूण हत्या को इन्क्रेज कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरीके से कन्या को देवी रूपक योजना के रूप में प्रोत्साहित किया है। उसी प्रकार से इस भ्रूण हत्या के बारे में क्राईम को कोग्नीजैंश घोषित किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे काम करने की किसी की हिम्मत न हो। जिस तरीके से हमारा लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है उसमें सुधार हो सके। चेयरमैन साहब, फरीदाबाद बहुत बड़ा इण्डस्ट्रीयल टाऊन था जिसका हैवी इण्डस्ट्रीज में वर्ल्ड ओवर नाम था लेकिन पिछली सरकार ने फरीदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक नगर को तबाह करके रख दिया था और आज आम भाषा में फरीदाबाद को फकीराबाद कहकर हंसी

[श्री ए०सी० चौधरी]

उड़ाई जाती है। कई प्रोग्राम्ज के बारे में इस अभिभाषण में अर्बन डिवलैपमैंट का जिक्र किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि महज शहर को बनाने के लिए सिर्फ रोड्ज तथा 2-4 इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत काफी नहीं है। सही तो यह है कि बिजली इण्डस्ट्रीज की जान है, उसका रॉ मैटीरियल है, इन्फ्रास्ट्रक्चर उसका एसैंशियल इन्ग्रेडियंट्स है। जब तक ये दोनों चीजें एवेलेबल नहीं होंगी, बाहर से हम उद्योगपतियों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ हमें उद्योगपतियों को कुछ माहौल और देना होगा, जिस तरह फरीदाबाद में बदरपुर का पुल है उसका बनना बहुत जरूरी है, बदरपुर एक ऐसा बोटलनैक बन गया है जहां 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम लगा रहता है जिसका नतीजा यह निकलता है कि जो बाहर से आने वाले उद्योगपति हैं जो उद्योग लगाने का चिंतन करते हैं कि वे जाएंगे कैसे? नतीजा यह निकलता है कि प्रोग्रैसिव स्कीम्ज का फायदा फरीदाबाद या हरियाणा को नहीं मिल पा रहा। सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि इस मामले में जिस तरह सैंट्रल गवर्नमैंट ने बाकायदा ग्लोबल टैण्डर्ज कर लिए लेकिन कुछ रुकावटों की वजह से अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ, मैं मुख्यमंत्री महोदय से अदब से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समस्या को फौरी तौर पर हल किया जाए। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि स्टेट लेवल पर जो काम शुरू हुए हैं उनमें इस काम को अपने हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी इस पुल को बनवाया जाए। क्योंकि शहर तब तक नहीं बनेंगे जब तक शहरी सुविधाएं न हों। एक तरफ तो सरकार ने चुंगी खत्म कर दी और चुंगी की भरपाई के लिए लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स लगा दिए लेकिन मैं हैरान हूँ कि चुंगी की भरपाई का मतलब जिस कमेटी को जितना पैसा चुंगी से मिल सकता था, उसके बदले उतना पैसा लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स से मिलना चाहिए था लेकिन फरीदाबाद कारपोरेशन को पिछले 10 सालों में पिछली सरकार ने कुल मिलाकर एक करोड़ 10 लाख रुपये दिए जबकि उसका हिस्सा 200 करोड़ रुपये बनता था, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। अगर मुख्यमंत्री जी के जो प्रोग्राम हैं उसमें इन बातों को समायोजित नहीं किया गया तो शहर नहीं बन पाएंगे इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को दिखवा कर इस का जितना हिस्सा बनता है वह दिलवाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो बेहतर यही होगा कि शहरों में दोबारा चुंगी लगा दी जाए। वरना शहर के कंसैप्ट को किताबों में पाओगे। शहर नहीं रहेंगे, शहर वर्स्ट स्लम बन जाएंगे इसलिए इस विषय में गहन चिंतन की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप जल्दी कन्कल्यूड करें।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं घड़ी के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं तीन आइटम्ज पर बोल चुका हूँ और दो आइटम्ज पर और बोलकर अपनी बात जल्दी ही खत्म कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You are a learned person and you have the capacity to speak. एक घण्टे की बात आप 5 मिनट में कैसे कर लेंगे।

श्री ए.सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष

महोदय, मैं हैल्थ प्वांयट पर सरकार की पोलिसी को एप्रीशिएट करूंगा। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एनवायर्नमैंट की गंदगी की वजह से आज कैंसर और हार्ट की प्रोब्लम्ज इतनी बढ़ गई है कि हर घर में एक मरीज पड़ा है और इन बीमारियों का इतना मंहगा इलाज है कि 3 से 5 लाख रुपये एक ओपरेशन पर लगते हैं, जिसे गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सही तो यह है कि हार्ट की बीमारी से ज्यादा उसके खर्चे का और उसके बिल का चिंतन मरीज को अधमरा कर देता है। सरकार ने इस बीमारी के लिए फण्ड्स का प्रावधान किया है, मैं आग्रह करूँगा कि ये फण्ड्स फौरी तौर पर देने के लिए कमेटी गठित की जाए ताकि जल्दी से जल्दी जरूरतमंद लोगों को इस फण्ड का फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यह लड़कियों का साल है, उस नाते से जहां तक लड़कियों के लिए कॉलेजिज का सवाल है तो इस मामले में मैंने पहले भी सरकार से प्रार्थना की थी और आज भी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए कुछ कॉलेजिज जरूर बनाए जाएं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हल्के में सीकरी गाँव वाले कॉलेज के लिए पूरी जमीन देने के लिए तैयार हैं और जो इस के लिए पैसे का प्रावधान रखा जाएगा वे पैसे भी वे लोग दे देंगे इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे कॉलेज की मंजूरी कर दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एरिया लेबर डोमीनेटिड ऐरिया है वहां स्लम पोकिट है और बहुत छोटे-छोटे अनएप्रूवड मकान बने हुए हैं मैं चाहूँगा कि सरकार उन लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से गाँव में डिलीवरी हट बना रही हैं उसी तरह झुग्गी झोपड़ियों में भी डिलीवरी हट का प्रावधान कर दिया जाए ताकि गरीब लोगों को इसका फायदा मिल सके। जो बेसिक सिविक एमनिटीज हैं वे झुग्गी झोपड़ियों में दे दी जाएं। पिछली सरकार ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है कि गरीबों को पानी के लिए और रोशनी के बल्ब की रिप्लेसमैंट तक का अधिकार नहीं मिलता था। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना आग्रह करना चाहूँगा कि इन चीजों का ध्यान रखते हुए इनका पूरा-पूरा प्रावधान किया जाए।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। सदन में जिस तरह का वातावरण विपक्ष के साथियों ने पैदा किया उसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूँगा कि प्रजातंत्र के अंदर जितना दायित्व सत्तापक्ष का होता है उतना ही दायित्व विपक्ष का होता है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता कि सत्तापक्ष जो भी कार्य करे उनका विपक्ष वाले विरोध करने के लिए कोई न कोई अड़ंगा डालते रहें। स्पीकर सर, हम चाहते हैं कि इस बारे अब कोई अच्छा हल निकले और विपक्ष के साथी ऐसे ही सदन का समय बर्बाद न करें। जो विघ्न यहां होता है उससे सदन का बहुत अधिक समय बर्बाद होता है। इस बारे में यदि आम जनता को पता चलेगा तो उन्हें महसूस होगा कि हम यहां आकर क्या कार्य करते हैं। जितना बुरा हाल यहां होता है इतना बुरा हाल तो गाँव की पंचायतों में भी नहीं होता। मैं विपक्ष के साथियों को अपनी सलाह नहीं दे सकता लेकिन अपने दिल की बात उनको जरूर व्यक्त कर सकता हूँ। स्पीकर सर, हमारी सरकार गतिशील और प्रगतिशील सरकार है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वह सरकार का दर्पण होता है, शीशा होता है। शुरू से आखिर तक मैं

16.00 बजे

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हर चीज को बहुत ठीक ढंग से दर्शाया गया है। यदि पिछले दस महीने की हमारी सरकार की सभी उपलब्धियों का मैं व्याख्यान करूंगा तो बहुत समय लगेगा। इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। उनके लिए मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके सहयोगी मंत्रियों को और सरकारी अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। स्पीकर सर, पिछली सरकार के समय में एक्सप्लायटेशन बहुत होता था और हर वर्ग का शोषण होता था। किसानों को पिछली सरकार के समय में किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया। वे लोगों का शोषण करते रहे और पाँच साल तक राज कर गए। उस समय लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ। अब हमारी सरकार ने लेबर पोलिसी बनाई है। मेरे विपक्ष के भाईयों ने उसकी भी आलोचना की। स्पीकर सर, अगर कोई किसी चीज की आलोचना करना चाहता है तो आलोचना आलोचनात्मक सुझावों के साथ करे लेकिन यह नहीं कि आलोचना ऐसे ही उल-जलूल बातों के साथ करे और कोई सुझाव सरकार को न दें और सदन का समय बर्बाद करें। स्पीकर सर, हमारी सरकार की लेबर पोलिसी बहुत बढ़िया पोलिसी है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुण्डली में राजीव गांधी एजूकेशन सिटी स्थापित करने का फैसला किया है यह बहुत सराहनीय फैसला है। इससे सारे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। इसके साथ मैं मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा महिलाओं का शैक्षणिक शिक्षा संस्थान खानपुर में है। यहां पर 7-8 हजार लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं। पहली जमात से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और लॉ तक की क्लासिज वहां लगती हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर महिलाओं का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। वहां पर 200 एकड़ जमीन भी गुरूकुल के पास है। सारी सुविधाएं वहां पर पहले से ही हैं और देहात के लोगों का भी बहुत रूझान है। इस बारे में कुछ दिनों पहले बात चली थी लोगों ने इसे बहुत सराहा कि वहां पर महिला विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान दें। स्पीकर सर, अब मैं कृषि के बारे में जिक्र करना चाहूँगा और क्रोप इन्श्योरैंस के बारे में कहना चाहूँगा कि फसल इन्श्योरैंस के लिए कुछ फसल और एरिया सलैक्ट करते हैं। मेरी गुजारिश है कि इसमें फसल और एरिया का सवाल नहीं होना चाहिए और सभी एरियाज में सभी क्रोप्स की इन्श्योरैंस होनी चाहिए तभी किसानों का आत्म विश्वास बढ़ेगा। स्पीकर सर, किसान अपने घर से अनाज निकालकर खेतों में डाल देता है और कई दफा उसे मिलता कुछ नहीं है इसलिए सभी क्रोप्स का इन्श्योरैंस होना चाहिए। हमारी सरकार ने कुछ कलस्टर स्थापित किए हैं उनमें विशेष तौर पर फरीदाबाद और पानीपत शामिल हैं। मैं गोहाना के बारे में कहना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि सभी लोग अपनी-अपनी कांस्टीच्युएंसीज के बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। सारे हिन्दुस्तान में निवार की सबसे बड़ी इण्डस्ट्री गोहाना में रही है तथा डिफैंस सर्विसिज में जितने भी टैन्ट जाते हैं वे टोटली गोहाना से जाते हैं लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मेरी गुजारिश यह है कि गोहाना के अंदर निवार के लिए कलस्टर स्थापित किया जाए तथा उसको उसी ढंग से डिवैल्प किया जाए जैसे कि पानीपत में आटो पार्ट्स के लिए किया गया है अथवा पानीपत में टैक्सटाईल के लिए किया गया है। गोहाना में इसी लाइन पर यह

कलस्टर स्थापित किया जाए। इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के बारे में यहां पर बहुत से लोगों ने बात कहनी थी। पिछली बार जब सैशन था तो हमने यहां पर यूनेनिमस प्रस्ताव किया था। मैं एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का डिविजन हो। हमारा हाई कोर्ट अलग से बने लेकिन वह हाई कोर्ट उसी बिल्डिंग में हो जिस बिल्डिंग में हाई कोर्ट वर्तमान में चल रहा है। जब विधान सभा पंजाब और हरियाणा की एक ही बिल्डिंग में हो सकती हैं और सिविल सैक्रेटेरिएट पंजाब तथा हरियाणा का एक ही बिल्डिंग में हो सकता है तो 60:40 के अनुपात में हाई कोर्ट को उसी जगह पर रखा जाए और उसी बिल्डिंग के हिसाब से उसमें हरियाणा का हिस्सा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे गोहाना का जो इलाका है वह टेल पर है और वहां पर पानी की बहुत मुसीबत है। वैसे मैं कैप्टन साहब को इस बात में बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इसके साथ ही बाकायदा एक प्वायंट पर बहुत ही गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। नहर के रास्ते पर बीच में जो गाँव आते हैं वहां के लोग पानी की चोरी करते हैं। कई लोग एम०एल०ए० के पास जाते हैं एम.एल.ए. साहेबान टैलीफोन कर देते हैं और आपस में लगातार लोग पानी की चोरी करते हैं। बेसिकली यह एक बीमारी है इसके लिए बाकायदा ढंग से कोई फोर्स ऐस्टेब्लिश की जाए जिससे गाँव के अन्दर पानी की चोरी न हो। अभी परसों यह बयान अखबार में आया है, अध्यक्ष चौटाला साहब गोहाना के अन्दर गए थे और वहां पर कार्यकर्त्ताओं की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। मुझे उनकी ऐसी भाषा के ऊपर हैरानी है उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है अखबार में यह बयान दिया है कि नई नहर खोदने से आन्तरिक जल युद्ध छिड़ जाएगा। स्पीकर साहब, मैं यहां पर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि यदि न्याय देने के कारण आन्तरिक युद्ध छिड़ जाएगा तो हम उस युद्ध के लिए तैयार हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अन्याय होगा तो युद्ध छिड़ जाएगा यह बात कोई कहता तो बात समझ में आने वाली थी लेकिन न्याय के लिए भी आंतरिक युद्ध छिड़ जाएगा यह बात बड़ी अजीब लगती है। मैं तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को मुकाबरबाद दूंगा कि उन्होंने हिम्मत की है दूसरा कोई आदमी ऐसा कर नहीं पाता। इस चीज पर कहीं पर कोई लाइन भी नहीं है। वे लोग जिनके वैस्टिड इन्ट्रस्ट हैं वे अपने लोगों को राजी करने के लिए कुछ भी कहें वरना 70 फीसदी पानी 30 फीसदी ऐरिया ले और 30 फीसदी ऐरिया को 70 फीसदी पानी मिले यह बिल्कुल उलट बात है। इस लिहाज से मैं यह कहूँगा कि इस किस्म की चीजों के बारे में न सोचने की बात है और न चिंता करने की बात है। मैं अपने विरोधी पक्ष के साथियों से भी कहूँगा कि हम यहां पर किस लिए आए हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। न कि उनके साथ अन्याय करने के लिए आए हैं। कोई किसी तरह की बात हो हमें खुलकर न्याय का साथ देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आज पार्टी लाइन पर हर वक्त चलना, आँख बंद करके पार्टी लाईन पर चलना यह शोभा की बात नहीं है। लोगों के बीच जाकर जो लोगों की भावनाओं का एक्सपलॉयटेशन करते हैं, विरोधी पार्टी के भाइयों को कम से कम यहां पर तो अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और न्याय के लिए अपनी बात कहनी चाहिए जिससे लोगों का भला हो। (विघ्न) एक मुद्दा कुछ समय से भूला हुआ है। जो अबोहर फाजिल्का के 107 गाँव हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। चण्डीगढ़ का जिक्र भी कम प्रॉयोरिटी पर नहीं है हमारा एस०वाई०एल० का मुद्दा प्रॉयोरटी पर है उसमें

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

कोई सन्देह की बात नहीं है लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि इन तीनों चीजों को बाकायदा इकट्ठा करके इनके लिए फाईट करने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार की सौदेबाजी में हमारे साथ कोई धोखा न हो जाए इसलिए इन तीनों चीजों पर हमारा पूरा क्लेम है। हमारा इन पर पूरा अधिकार बनता है। स्पीकर सर, लास्ट प्वायंट पर मैं एजुकेशन के बारे में कहूँगा। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत पुरानी और अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड मैकाले ने क्लर्क पैदा करने के लिए यह शिक्षा नीति बनाई थी। अँग्रेजों के समय यह शिक्षा नीति जो कि जॉब ओरिऐंटिड नहीं है बल्कि सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए यह शिक्षा पद्धति चलाई गई थी। जो एजुकेशनिस्ट हैं जो बाकायदा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी एक कमेटी स्थापित करें क्योंकि हरियाणा ने बहुत सी चीजों में शुरूआत की है और बहुत सी चीजों में हम आगे हैं। पिछले दस ग्यारह महीनों के कामों से हम और भी आगे स्पीडअप हुए हैं लेकिन एजूकेशन के मामले में हम अभी भी पीछे हैं। किसी भी प्रदेश ने इस शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस बारे में कदम उठाए जाएं और एक कमेटी स्थापित की जाए। इस कमेटी को आप टाईम बाउंड करें कि वह एक या दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे। इस कमेटी से सुझाव लें ताकि सारे सिस्टम में चेंज आए। हमारी एजुकेशन जॉब औरिएन्टेड होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होने से काफी फर्क पड़ता है और अभी हम जो बेरोजगार पैदा कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। स्पीकर साहब, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार के विजन 2020 को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा वह काबिलेतारीफ है क्योंकि उन्होंने चहुँमुखी विकास का ध्यान रखा है। इण्डस्ट्रीज और ऐग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो हमारी सरकार ने प्रोग्राम दिए हैं उससे सभी को लाभ मिलेगा। इसी तरह से किसानों के जो 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ हुए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। किसान इस बात को लेकर आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि वे इन बिलों को भरने में असमर्थ थे। इसी तरह से किसानों को गन्ने का भाव 135 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया गया है। इतना ज्यादा गन्ने का रेट आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं बढ़ा है जितना इस बार बढ़ाया गया है। हमारे एरिये के किसानों को भी इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी प्रकार से जो लैंड सरकार द्वारा ऐक्वायर की जाती है उसका भी कम्पनसेशन सरकार ने बढ़ाया है। पहले यह बहुत ही कम होता था अब इसको काफी बढ़ा दिया गया है। फिर भी यह मुआवजा मार्किट रेट से काफी कम हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि जो हमारे टाउंज हैं और जो उनके पास हमारी जमीन लगती है वह काफी महंगी हो गयी है। किसानों से जो जमीन ली जाती है वह मार्किट रेट से कम में ली जाती है। हुड्डा तो प्रौफिट नहीं लेता लेकिन जिनको प्लाट्स दिए जाते हैं उनको बहुत फायदा होता है इसलिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जमीनों के रेट और बढ़ने चाहिएं। इसी प्रकार से

इण्डस्ट्रीज पोलिसी को भी और ज्यादा सिम्पलीफाई किया गया है इससे इण्डस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब हरियाणा में प्राइवेट उद्योग और ज्यादा लगेंगे। इससे रोजगार की समस्या भी काफी हद तक हल होगी। यह बहुत ही अच्छा काम है। एक करोड़ रुपये कंसलटैन्ट मैनजमैन्ट वालों को दिए गए हैं। लेबर पोलिसी को भी आसान बनाया गया है। इससे अब इण्डस्ट्रीज और लेबर दोनों में आपस में अच्छी समझ से फैसले होंगे। अब इन दोनों में दिक्कत कम हो जाएगी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी 268 एकड़ में बनाने जा रहे हैं इससे भी दूरगामी लाभ होगा और इससे हरियाणा में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। हमारी सरकार के वक्त में फसलों का उत्पादन भी कम नहीं रहा है। अभी तक मैक्सिमम 40.72 लाख उत्पादन हुआ है। जो सरकार ने खरीद की है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आयी है। सभी किसान और आढ़तियों को इससे कोई कठिनाई नहीं हुई है। मण्डियों में सुचारू रूप से काम चला है। बिजली के संकट को देखते हुए 4000 हजार मैगावाट बिजली बनाने का काम शुरू किया गया है। यह बहुत ही अच्छा फैसला है। 600 मैगावाट बिजली पैदा करने का संयंत्र यमुनानगर में बनना शुरू हो गया है। इसी तरह से सब-स्टेशंज बनाने के लिए भी सात सौ करोड़ रुपये रखे गये हैं। हमारे इलाके में भी तीन सब-स्टेशंज बनेंगे। सलारपुर में 220 के०वी०, लोहड़ा में 66 के०वी० और मचाना में 66 के०वी० का सब-स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे को तीन सब-स्टेशन दिए हैं। एक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की जो 70 करोड़ रुपये की योजना है उससे गांवों को बिजली मिलेगी, इससे किसानों को गांव के लोगों को जो बिजली की दिक्कत रहती है उससे उनको फायदा मिलेगा। एन.एच. 1, पानीपत और अम्बाला जीरकपुर हाइवे की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी और मानेसर पलवल हाइवे का काम होगा यह भी बहुत सराहनीय है। इसके अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ को मैट्रो से जोड़ा जायेगा। यह भी बहुत अच्छा काम है। इरीगेशन कैनाल का 25 परसेंट बजट बढ़ा दिया गया है इससे दादूपुर नलवी का काम पूरा हो जाएगा इससे यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सभी सदस्य जिनके नाम बोलने के लिए समय देने के लिए आए थे, वे सभी बोल चुके हैं। इस चर्चा में 331 मिनट में 26 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। कुछ साथी जो बोलने से वंचित रह गए हैं उनसे मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि वे बजट पर डिटेल में अपनी बात कहें। Now, Hon'ble Chief Minister will give the reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां विधान सभा में दिया, उसका मैं आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने किस प्रकार से हर पहलू, हर वर्ग को पिछले साल में जो कार्य किए, उनका उन्होंने अभिलेख किया और इस बारे में बहुत सारे साथियों ने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उनका भी मैं धन्यवादी हूँ और प्रयास करूंगा कि जो भी सुझाव आए हैं हम उनके ऊपर विचार करें और जो कर सकें, करें। हमने प्रदेश को स्वच्छ, क्लीन, ट्रांसपेरेंट, कुशल प्रशासन देने का प्रयास किया है और ठोस कदम इस बारे में हमने उठाए हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, दलित, पिछड़े

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

वर्ग और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हमने बहुत सारे अहम् फैसले लिए हैं। इस पिछले वर्ष में हमें बहुत अच्छा रिसपौंस लोगों का मिला है और कार्य बहुत अच्छे और सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश के हित में नवनिर्माण और विकास के लिए एक मजबूत नींव हमने डाली है। जैसे सभी सदस्यों ने कहा। जो चुनाव में नतीजे आए वह हरियाणा के लोगों ने देखे। आपके सामने विकास का जो कार्य था, गत वर्ष, वह हरियाणा में रुका हुआ था। लोगों ने जिस आशा से यह सरकार बनाई है उसके विकास के लिए जो विकास के कार्य के पुर्जे टूटे पड़े थे, उसके टायरों से हवा निकली पड़ी थी उसको दुरुस्त करके टायर लगाकर नये टायर चढ़ाकर विकास की कार्यवाही शुरू की है। अब हरियाणा प्रदेश का विकास तेजी से शुरू होगा। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए किसी प्रदेश को, देश को, किसी भी वर्ग को प्रगति करना है उसके लिए 3 चीजें मुख्य रूप से जरूरी हैं। सड़क भी बन जाती हैं, नहरें भी बन जाती हैं और कार्य भी सब हो जाते हैं लेकिन अगर तीन चीजों में से एक चीज भी नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता। प्रदेश के विकास और कानून-व्यवस्था के सवाल पर यहां पर चर्चा हुई। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और जो भय और असुरक्षा का वातावरण पूरे प्रदेश में था उससे आज हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर हरियाणावासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और यही कारण है कि हरियाणा में लोग अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। जैसा कि इन्दौरा जी ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश में भयमुक्त अधिकारी हो गये हैं और वह किसी की परवाह नहीं करते। इनकी यह बात ठीक है मैं इनसे सहमत हूँ। यही हम भी चाहते थे कि अधिकारी भयमुक्त हों। पिछली सरकार के प्रशासन में अधिकारियों को किसका भय था, अधिकारियों को अपराधियों का भय होता था। लेकिन आज उन अपराधियों का भय अधिकारियों में नहीं है। भय के कारण कोई भी अधिकारी प्रगति, विकास और जनहित का कार्य नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था और उनको सरकार का संरक्षण भी प्राप्त था। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद 12 ऐसे अपराधियों को छोड़ा जिन पर कई-कई मर्डर केस चल रहे थे। लेकिन आज की सरकार ने अधिकारियों को और पूरे प्रशासन को भयमुक्त किया है। जनहित के कार्य करने के लिए सरकार जो जनहित की नीति पर चलती है उनको लागू करने के लिए भयमुक्त प्रशासन जरूरी है। अब अधिकारियों को वह भय नहीं रहा जैसे पहले होता था। अगर यह नीति आप लागू करेंगे तो उससे आम आदमी को फायदा नहीं होगा। इसमें अगर विशेष लाभ नहीं हुआ तो उनके डण्डे पड़ेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब हमने प्रशासन को पूरी तरह से भयमुक्त किया है इसका लाभ पूरे प्रदेश को भी मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा मैंने कहा कि बिजली की समस्या हमारे सामने हैं। इसके क्या कारण है? आज हरियाणा प्रदेश को बने हुए 40 साल के लगभग हो गये हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लम्बे-लम्बे समय तक प्रदेश में सरकारें रहीं लेकिन इन 40 सालों में हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 4033 मैगावाट किया गया है (विघ्न)

Mr. Speaker : No running commentary, Mr. Sadhaura ji, Leader of the

House is replying. Please maintain the dignity of the House.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथियों को बताना चाहता हूँ कि इनको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए पूरा समय दिया गया था लेकिन जब इनका बोलने का समय आया था तब ये नहीं बोले। अब कृपया ये सुनने का कष्ट करें। पहले मैं 40 साल की बात करना चाह रहा था। पिछले पाँच साल में क्या हुआ पिछले पाँच साल में केवल पानीपत थर्मल प्लांट की 7वीं यूनिट 250 मैगावाट की लगाई गई थी और जब से यह लगाई तब से वह खराब पड़ी हुई थी। इससे ये माननीय विपक्ष के सदस्य समझ लें कि पिछले पांच साल में बिजली का कितना कार्य हुआ था। लेकिन मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि आज 3.25 बजे पानीपत की 7वीं यूनिट ने कार्य करना शुरू कर दिया है जोकि 24 घण्टे बिजली का उत्पादन करना शुरू कर देगी। (विघ्न) इन्दौरा साहब, झूठे वायदे करने के हम आदी नहीं हैं। आप 30 अगस्त, 2004 का 'दि हिन्दू' अखबार उठाकर देखें। उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि 31 दिसम्बर, 2004 को हरियाणा पॉवर कट फ्री प्रदेश हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वे बिजली तो 4000 मैगावाट हरियाणा में पैदा कर रहे हैं जबकि प्रदेश में कुल मांग 8000-9000 मैगावाट की है जोकि हर साल बढ़ती जा रही है तो कैसे हरियाणा पॉवर कट फ्री प्रदेश हो जायेगा। उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की क्योंकि प्रदेश में चुनाव सिर पर खड़े हुए थे लेकिन हमारा यह कार्य नहीं है। हमारा यह मानना है कि हम लोगों से झूठे वायदे नहीं करते। सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जब तक हम पूरी बिजली पैदा नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन में तो इतनी बिजली पैदा हो नहीं सकती, 24 घण्टे में तो बिजली पैदा नहीं हो सकती। अब जहाँ भी कोई प्रोजैक्ट लगायेंगे उसको पूरा होने में 3-4 साल तक का समय तो लग ही जायेगा। सदन को इस बात को जानकर खुशी होगी क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह बात कही है कि हम आने वाले साढ़े तीन साल या चार साल में हरियाणा में 5000 मैगावाट और बिजली पैदा करेंगे ताकि जो 8000-9000 मैगावाट की जो मांग है वह पूरी हो सके। 1065 मैगावाट का प्लांट फरीदाबाद में जिसका शुभारंभ कर चुके हैं लगेगा, 180 मैगावाट का प्लांट झज्जर में लगेगा। इसके लिए टाटा के साथ एम०ओ०यू० हमने दस्तखत किया है, 600 मैगावाट थर्मल बेस्ट यमुनानगर में, हिसार में 1080 मैगावाट की परियोजना के लिए जिंदल से हमारी बातचीत चल रही है और 500 मैगावाट का गैस बेस्ड प्लांट पानीपत में लगेगा। इसके साथ-साथ एक और फैसला हमने अभी किया है कि 1000 मैगावाट का ज्वायंट सैक्टर थर्मल प्लांट हिसार में लगेगा ताकि आने वाले साढ़े तीन-चार सालों के अंदर-अंदर कम से कम 5000 मैगावाट और बिजली पैदा कर सकें। बिजली की चर्चा हो रही है, ये आंकड़े हैं, पिछले साल यह सरकार आने से पहले दिसम्बर तक और अब तक बिजली आप देखेंगे तो हमने 7 प्रतिशत ज्यादा बिजली विभिन्न सैक्टरों में हरियाणा के लोगों को दी है। पहले तीन-तीन दिन बिजली नहीं आती थी यह सबको मालूम है। गांव में तीन-तीन दिन बिजली गुल रहती थी। आज किसान की कोई भी फसल चाहे वह धान की फसल है चाहे गेहूँ की फसल है जो ट्यूबवैल्ज पर निर्भर हैं हमने खराब नहीं होने दी। 6 से 8 घण्टे तक हर ट्यूबवैल को बिजली दी गई है। इस प्रकार जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात है उसको स्ट्रैंथन करने

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए 7000 नए ट्रांसफार्मर और 2700 जो वर्तमान ट्रांसफार्मर हैं उनको अपग्रेड करने की योजना हमने बना रखी है। इसी प्रकार पानी की बात है, सिंचाई की बात है, एस०वाई०एल० पर हमारे साथियों ने चर्चा की, एस०वाई०एल० के बारे में पिछली बार भी मैंने कहा था और आज मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहता हूँ कि एस०वाई०एल०के मामले में जितना विलम्ब हुआ, जो हरियाणा के लोगों को हक का पानी नहीं मिला उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी इनेलो और भारतीय जनता पार्टी है। यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कही गई है जिसने हरियाणा के हित में फैसला दिया उस फैसले का आधार दो बातें थीं--एक तो इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव लौंगोवाल समझौता और उसका विरोध किसने किया। उसका विरोध तत्काल लोकदल ने किया था जिसके अध्यक्ष चौधरी देवीलाल जी थे लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने न्याय युद्ध का नाम चलाकर उसका विरोध किया था? अगर ये विरोध न किया होता तो हरियाणा को कभी का अपने हक का पानी मिल जाता। जो भी एस०वाई०एल० पर कार्य हुए वे सब कांग्रेस के राज में हुए, चाहे इंदिरा गांधी ने उसका शुभारंभ किया हो चाहे राजीव लौंगोवाल समझौते के बाद केन्द्र की परियोजना हो, केन्द्र की तरफ से 700 करोड़ रुपए इस पर लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो साल तक श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका समर्थन रहा लेकिन उस समय उन्होंने यह फैसला ठण्डे बस्ते में रखा। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आई और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार आते ही कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे जब वे प्रधानमंत्री को मिले तो उन्होंने यह फैसला लागू करवाया और केन्द्र सरकार ने फैसला किया कि बाकी का एस०वाई०एल० का कार्य पंजाब से न कराकर सी०पी०डब्ल्यू०डी० से कराएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वह फैसला होते ही पंजाब ने गैर कानूनी बिल पास किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और इनका भी डायरैक्ट या इनडायरैक्ट समर्थन रहा है। (शोर एवं व्यवधान) अगर आपको शिष्टाचार का ख्याल हो तो बीच में न बोलें क्योंकि जब आप बोले तो मैं बीच में एक बार भी नहीं बोला, इसलिए आप सुनने की हिम्मत रखें। मैं समझता था कि इन्दौरा साहब पार्लियामैंट से आए हैं आप सबको कुछ सिखाएंगे लेकिन लगता है उलटा इन पर असर हो रहा है (शोर एवं व्यवधान)।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार हम पर लांछन न लगाएं, मैंने हमेशा सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कही है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये सुनने का कष्ट करें, ये जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में इनको नहीं टोका। ये सुनने की हिम्मत रखें। आज हरियाणा की जो दुर्दशा है उसके लिए पूर्ण रूप से ये दोषी हैं, एस०वाई०एल० का जो पानी हरियाणा को नहीं मिल पाया और हरियाणा के लोगों के साथ जो धोखा हुआ है उसके लिए पूर्ण रूप से ये दोषी हैं। अब तो खिसयानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम नहर बनवायेंगे और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। जिस समय पंजाब सरकार ने गैर कानूनी

बिल हमें पानी न देने के बारे में पास किया उस समय मैं सांसद था। हम प्रधानमंत्री जी से मिले और अपना हक रखा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब पार्लियामैंट में भी रहे हैं इनको यह शोभा नहीं देता कि ये बीच में मुझे टोका-टाकी करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, प्लीज आप बैठें। आप चेयर की परमिशन के बगैर कैसे खड़े हो गये? (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat. Hon'ble Chief Minister is giving the reply. (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इनको तो चेयर की परमिशन के बगैर खड़े होने की आदत हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एस०वाई०एल० नहर का ज्यादातर काम कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ। लेकिन यह बात तो चौधरी बंसी लाल जी ने भी मानी है कि एस०वाई०एल० नहर का 80 प्रतिशत काम चौधरी देवी लाल जी के समय में हुआ था। यह रिकॉर्ड की बात है आप चाहें तो इसी सदन की कार्यवाही निकलवाकर देख सकते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है जो तथ्य हैं वे तथ्य ही रहेंगे। किसी ने क्या कहा इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ वे ही तथ्य हैं। यदि इन्दौरा साहब के पास कोई तथ्य हैं तो उनको ये सामने लेकर आयें। अध्यक्ष महोदय, ये स्वयं ही बता दें कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी कौन सी पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। इनको मालूम है कि ये कौन सी पार्टी से थे। इनको यह भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और वह किस आधार पर हरियाणा के हक में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यदि इनको नहीं मालूम तो मैं बताना चाहूँगा कि यह फैसला इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव लौंगोवाल समझौते के आधार पर हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दौरा साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले ये उस फैसले को पढ़ लें उसके बाद चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एस०वाई०एल० नहर के काम में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए ये लोग पूर्ण रूप से दोषी हैं। आज के दिन हरियाणा में जो उपलब्ध पानी है उसके न्यायोचित बंटवारे के लिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है और उसके लिए हम 109 कि०मी० लम्बी नई नहर लगभग 260 करोड़ रुपये की लागत से बनवायेंगे। इस बारे में जैसा कि माननीय सदस्य मलिक साहब ने बताया कि अखबारों में इनके नेताओं ने किस तरह के बयान दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि सरकारें जनता को न्याय देने के लिए होती हैं और इनको न्याय का साथ देना चाहिए। इस मामले को लेकर आज तक कोई भी असहमति कहीं पर नहीं हुई और हम चाहते हैं कि जिन लोगों का इस पानी पर हक है वहां तक, अंतिम छोर तक यह पानी पहुंचाया जाये। लेकिन मेरे विपक्ष के साथी ऐसा नहीं चाहते कि पिछले कई सालों से जिनके साथ अन्याय होता आ रहा है अब उनको न्याय मिले। अध्यक्ष महोदय, कोई भी बात हो इन्दौरा साहब तो यहां खड़े होकर कहने लग जाते हैं कि सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। इनको मालूम नहीं कि शर्म की बात क्या है। शर्म की बात तो यह है कि आज हरियाणा की जनता ने इनको विपक्ष का

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

नेता बनने लायक भी नहीं छोड़ा। इसलिए शर्म तो इनको और इनके नेता को आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने तो नहर के मामले में बरसौला माईनर के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हम नकली पत्थर लगाने में यकीन नहीं रखते। यह तो बहुत आसान काम है क्योंकि इसमें तो सिर्फ 200-250 ईंटें ही लगती हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो दिसम्बर, 2004 तक जब इनकी सरकार थी, नाबार्ड के पैसे में से उस समय नहरों के रख-रखाव पर कुल 32.43 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और हमारी सरकार आने के बाद इस दिसम्बर तक 73 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जोकि इनके द्वारा खर्च किए गए पैसे से डबल हैं। अध्यक्ष महोदय, हर वर्ग के साथ-साथ हमारी सरकार ने किसानों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। जिस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे और हम विपक्ष में बैठे थे उस समय चौटाला साहब कहा करते थे कि हरियाणा के किसानों को गन्ने का सबसे ज्यादा भाव उनकी सरकार दे रही है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि सबसे ज्यादा गन्ने का भाव तो किसानों को आज दिया जा रहा है। इन्होंने 117 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव किसानों को दिया था जबकि हमने उसमें एक दम 18 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करके 135 रुपये प्रति क्विंटल का भाव कर दिया है। इतनी अधिक वृद्धि गन्ने के भाव में आज तक नहीं हुई। हम चाहते हैं कि किसान को गन्ने की प्रोक्योरमैंट पर अच्छे पैसे मिलें लेकिन अपने आपको किसान हितैषी कहने वालों ने 6 साल तक कोई पैसा नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जब भी प्रोक्योरमैंट हुई तो मण्डी में जो लूट मची, जो गदर मचा वह सब को मालूम है। हमारे समय में सरसों की प्रोक्योरमैंट 3.06 मिलियन मीट्रिक टन हुई जबकि इनकी सरकार के समय में केवल 75 हजार मीट्रिक टन प्रोक्योरमैंट हुई। इसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि सब बंगलिंग होती थी क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इनके वक्त में किसान सरसों पैदा ही नहीं करते थे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पैडी की प्रोक्योरमैंट में भी धांधली हुई। पिछले वर्ष 2005 में जो पैड़ी की प्रोक्योरमैंट हुई वह 33.53 लाख टन हुई। 23.53 लाख से 33.53 लाख टन पैडी हमने प्रोक्योर की और इससे सब लोग सन्तुष्ट थे। पूरे हरियाणा में सभी किसान सन्तुष्ट हैं। इसी प्रकार से जब नैचुरल कैलेमिटी हुई तो उसका मुआवजा भी हमारी सरकार द्वारा दिया गया। नैचुरल कैलेमिटी में ओलावृष्टि हुई थी। इनकी सरकार के वक्त में भी जो ओलावृष्टि हुई थी उसका एन्हासड कम्पनसेशन हमने लोगों को दिया है। जितना कम्पनसेशन हमने दिया है वह ऑल टाइम एक रिकॉर्ड है। मैं उम्मीद रखता था कि इन्दौरा साहब की तरफ से सदन के पटल पर जो भी कागज आएगा वह पूरी तरह से पढ़कर दस्तखत होकर आएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब मेरे साथ सांसद रहे हुए हैं और इस प्रकार की सारी चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं इसलिए मैं इनसे यह उम्मीद रखता था कि कम से कम ये जब भी कोई दस्तखत करेंगे तो पढ़ कर दस्तखत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नोटिस ऑफ अमैंडमैंट दिया और ये 18-20 मिनट बोले लेकिन नोटिस ऑफ अमैंडमैंट पर इन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। इसका मतलब यह है कि इन्होंने बगैर पढ़े ही उस पर दस्तखत कर दिए। नोटिस ऑफ अमैंडमैंट के बारे में इन्होंने एक भी लफ्ज नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब 42 मिनट बोले हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि इन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं है ये बड़े ही काबिल और योग्य व्यक्ति हैं। इसका कारण मैं समझता हूँ यह है कि बगैर पढ़े इन्होंने दस्तखत तो कर दिया लेकिन जब पढ़ कर देखा तो यह पाया कि सारी बातें तो गवर्नर साहब ने अभिभाषण में उठाई हुई हैं इसलिए ये किस बात पर चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी चौधरी इन्दौरा साहब को यह मश्विरा दूंगा कि बगैर पढ़े किसी कागज पर दस्तखत न किया करें।अब बाहर से कोई चीज भेज दी और ये बिना पढ़े उसको दस्तखत करके असैम्बली के पटल पर रख दें तो ऐसा ठीक नहीं है (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप यह बताएं कि क्या आपने नोटिस ऑफ अमैंडमैंट पर कुछ बोला है और अगर आपने कुछ नहीं बोला तो बात समाप्त? He wants to justify. उनका ऐलिगेशन यह है कि आपने जो नोटिस ऑफ अमैंडमैंट दिया था अपने 44 मिनट्स के भाषण में आपने उसके बारे में एक भी बात नहीं उठाई। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन तो लें। (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनके भाषण का रिकॉर्ड आप मंगवा लें (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Mr. Indora, now take your seat please. आपको बोलने के लिए पलण्टी ऑफ टाइम दिया गया था (विघ्न) अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Please maintain the dignity of the house. (Interruptions) इन्दौरा साहब, सदन की गरिमा को बनाए रखें। लोग आपके व्यवहार को देख रहे हैं इसलिए मेहरबानी करके आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये मेरे साथ पार्लियामैंट में भी रहे हैं वहां पर तो मैंने इनको कभी भी खड़े होते हुए नहीं देखा लेकिन यह बात तो हमें बता दें कि हर बात पर खड़ा होना इन्होंने किससे सीख लिया, यह किस की सीख है? अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की जरूरत है। जैसा मैंने क्रैडिबिल्टी के बारे में कहा और जो कांस्टीच्यूशनल ईस्टीच्यूशन्ज हैं उनमें असैम्बली भी एक है। जो डैमोक्रेटिक इन्स्टीच्यूशन्ज हैं हमें उनकी क्रैडिबिलटी कायम करनी है और इसके लिए सब मिल-जुल कर काम करेंगे, इसमें इनका सहयोग चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार ये कहां से सीख कर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बिजली की बात कही, पानी की बात कही। पानी की जो नहर बनाने की बात हमने कही 2000 क्यूसिक पानी की, इसकी कैपेसिटी वहां तक जायेगी। आज बेरोजगारी की समस्या सबसे गम्भीर समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हमें करना है। इसमें केवल पढ़े-लिखे लोगों को ही रोजगार देने की बात

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

नहीं है अब सबको रोजगार देना है यह सबको मालूम है और ये भी सारी बात को समझते हैं। झूठे वायदे कोई करता रहे या लोगों को कुछ कहता रहे लेकिन बेरोजगारी का समाधान केवल सरकारी नौकरियां नहीं हैं क्योंकि सारे लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति केवल खेती पर भी निर्भर नहीं रह सकता है। इस समस्या का क्या समाधान हो, इसका समाधान केवल यह है कि प्रदेश का औद्योगिकरण हो, यहां पर बड़े-बड़े यूनिट्स लगें। अध्यक्ष महोदय, अगर एक बड़ा यूनिट लगता है तो दो हजार छोटे यूनिट्स लगते हैं। मेरा कोई बेरोजगार भाई छोटी यूनिट लगाएगा, कोई कारखाने में नौकरी करेगा। कोई सरकारी नौकरी निकलेगी तो वह उसमें जाएगा या यदि वह अपना कोई छोटा-मोटा धंधा करेगा तभी बेरोजगारी दूर हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यदि हरियाणा में अपना कोई कारखाना लगता है तो इसके लिए जमीन किसकी जाती है यह जमीन किसानों की जाती है, किसानों की जमीन ही अधिगृहीत की जाती है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में यह पहली मिसाल है और मैं इस बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण भी दे सकता हूँ कि जब आपकी यह सरकार बनी तो हमने अपनी पहली या दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया कि आज के बाद अगर कोई भी किसानों की जमीन किसी भी सरकारी कार्य के लिए सरकार अधिगृहीत करेगी तो सरकार की तरफ से किसानों को फ्लोर रेट दिए जाएंगे। हमने फ्लोर रेट फिक्स कर दिये कि एन०सी०आर० की जमीन का रेट अलग होगा और एन०सी०आर० के बाहर की जमीन का रेट अलग होगा। शायद भाई राम कुमार गौतम या दूसरे साथी यह कह रहे थे कि कुंडली में जमीनों के भाव बहुत हो गये हैं और किसानों को कम दाम दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने फ्लोर रेट फिक्स किए हैं मैक्सिमम रेट तय नहीं किए हैं। वह तो जमीन के मालिक की मर्जी है कि वह आगे एनहान्समैंट करके जितना मर्जी चाहे रेट ले सकता है। अगर वह दो करोड़ रुपये फिक्स करेगा तो उसको दो करोड़ रुपये मिलेंगे और यदि वह एक करोड़ रुपया फिक्स करेगा तो उसको एक करोड़ रुपये मिलेंगे। लेकिन हमने तो कम से कम रेट फिक्स किए हैं। कहीं पर यह रेट पाँच लाख रुपये हैं और कहीं पर साढ़े बारह लाख रुपये का रेट हमने फिक्स किया है। इससे किसान संतुष्ट भी है क्योंकि उसको बहुत लाभ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुंडली से पलवल एक्सप्रेस हाई-वे 135 किलोमीटर लम्बा रास्ता है दिल्ली के तीनों तरफ बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी ग्लोबल कोरीडोर बनाने की योजना है। इन्दौरा साहब, जब आपकी सरकार थी उस समय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह लिखित में है कि उस समय जो 3300 एकड़ से ज्यादा जमीन ऐक्वायर हुई थी और उसके लिए हरियाणा सरकार से जो जमीनों के मालिकों को कम्पनसेशन मिलना था, वह 168 करोड़ रुपया था। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी किसान को दो लाख रुपये, किसी किसान को ढाई लाख रुपये और यदि कहीं पर ज्यादा अच्छी जगह हो तो पाँच लाख रुपये किल्ले के हिसाब से सरकार ने उस समय ऑफर कर रखा था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने यह फैसला किया कि जो फ्लोर रेट हमने तय किए हैं उससे कम हम किसी को नहीं देंगे। स्पीकर साहब, केन्द्र सरकार ने हमारी इस बात को माना भी और इसका कितना लाभ हुआ है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, एक ही परियोजना में जहां किसानों को पहले 168 करोड़ रुपये मिलने थे वहीं अब 650

करोड़ रुपये किसानों को मिलेंगे। यानी 500 करोड़ रुपये का फायदा एक ही परियोजना में किसानों को मिलेगा। इस तरह से आने वाले समय में किसानों को हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इस तरह से हमने यह फैसला लिया है इसलिए सबको इस बात को मानना चाहिए। जो भी धरती से जुड़ा हुआ है, हरियाणा का सपूत है वह इस बात को मानेगा। लेकिन इन्दौरा साहब, आपको न तो किसी की क्रिटीसिज्म आती और न ही किसी की ऐप्रेशिएशन आती। अब इसमें मैं क्या करूं? (विघ्न) यह तो केन्द्र सरकार का मामला है इसमें यू०पी० की सरकार भी, दिल्ली की सरकार भी और हरियाणा सरकार भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, इसका क्रियान्वयन हमने ही किया है। ये लोग तो खाली ऑफर ही ऑफर करके गए थे। जिस प्रकार से वहां के जमीनों के मालिकों को लूटा जा रहा था उसको सब अच्छी तरह से समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, तीसरा हमारा खास ध्यान शिक्षा की तरफ रहा है इसलिए हमारी सरकार आने के बाद हमने शिक्षा के लिए जो बजट दिया वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछली सरकारों के मुकाबले में 66 परसेंट की एनहान्समैंट हमने शिक्षा के मामले में की है क्योंकि जहां तक शिक्षा का सवाल है इसके बारे में एक बहुत बड़े फिलोस्फर ने यह लिखा है कि अगर किसी समाज को एक साल जीवित रहना है तो वह फसल लगा ले, दस साल जीवित रहना है तो वह पेड़ लगा लें और अगर सदियों तक जीवित रहना है तो आने वाली पीढ़ियों को वह शिक्षा दे दे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अगर सदियों तक इस समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पर हमको ध्यान देना ही होगा। इसीलिए हमने शिक्षा पर ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने कुंडली में राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी बनाने का फैसला लिया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं का शिक्षा में पूरा साथ होना जरूरी है। जब तक महिलाओं में शिक्षा नहीं आएगी, हमारी बराबर की शिक्षा उनमें नहीं होगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक महिला पढ़ती है तो दो परिवारों में शिक्षा जाती है। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जैनरेशन है वह मुकाबला नहीं कर सकेंगी। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। अगर किसी चीज का कम्पीटिशन करना है या विकास करने की हमारी कम्पेटेटिव इच्छा है तो उसका एक ही रास्ता है कि शिक्षा में जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। जब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगी तब तक हम आगे विकास नहीं कर सकते। हम जो राजीव गांधी एजूकेशन सिटी बना रहे हैं उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बच्चे आएंगे उसमें हमारी तरफ से एक ही शर्त लगाई जाएगी कि जितने बच्चों का दाखिला हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मैडीकल में हो या बायो टैक्नोलॉजी में हो, जो अलग-अलग होगी और जितने बच्चों का दाखिला हो, उसमें से कम से कम 20 से 25 प्रतिशत बच्चे हरियाणा प्रदेश के हों। हम हों न हों लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हरियाणा का नाम ऊपर उठे, इसी वास्ते हमने फैसला लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक मॉडल स्कूल होगा। इसी तरह से इन्होंने टीचर्स की बात की है। जिस प्रकार से इनके समय में जे०बी०टी० की सलैक्शन हुई, उसका आज तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। सब इस बात को जानते हैं। क्या अनुपात था, कितने विद्यार्थियों के पीछे एक टीचर था, 60 विद्यार्थियों के पीछे एक टीचर था। हमने यह सरकार आने के बाद फैसला लिया और 60 से घटाकर 40 अर्थात् 1 : 40 की रेशो करने का फैसला लिया और सारे टीचर्स की भर्ती का फैसला किया। शिक्षा के मामले में काम तो ये लोग छोड़ गए थे और पूरे

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हम कर रहे हैं। (विघ्न) आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ हो जाते हैं। आप की पार्टी की एक बात मैं आपको बताता हूँ। यह बात आप लोगों को मालूम है कि एक बार इनकी पार्टी में चौधरी चरण सिंह भी थे वे राष्ट्रीय नेता थे, चौधरी देवी लाल थे और डॉक्टर सरूप सिंह भी थे। आपकी यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। जब टिकटों के बंटवारे की बात हुई तो चौधरी चरण सिंह जी ने इसके लिए दो मैम्बरी कमेटी बना दी। अब चौधरी देवी लाल और डॉक्टर सरूप सिंह ने यह फैसला करना था कि टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है और वैलिंगटन रोड़ पर इनका दफ्तर था। चौधरी चरण सिंह जी के पास कोई टिकट लेने चला गया और कहने लगा कि चुनाव आ रहे हैं मेरे को टिकट दो तो चरण सिंह जी ने कहा कि टिकटों के बंटवारे के लिए तो मैंने कमेटी बनाई हुई है। चौधरी देवी लाल और डॉक्टर सरूप सिंह के पास इस काम के लिए जाओ तो वह बोला कि गड़बड़ हो गई है। मैं ग्रेजुएट हूँ, बी०ए० पास हूँ। तो वह बोले कि बी०ए० पास है तो क्या हो गया तो वह बोला कि वहाँ तो बड़ी समस्या हो गई है, वहाँ झगड़ा हो गया है। चौधरी देवी लाल दसवीं पास हैं इसलिए 10वीं से ऊपर पढ़े लिखे की ऐप्लीकेशन नहीं ले रहे और डॉ० सरूप सिंह एम०ए० पास हैं इसलिए एम०ए० से नीचे की क्वालिफिकेशन वालों की ऐप्लीकेशन नहीं ले रहे और मैं बी०ए० पास हूँ मैं कहाँ जाऊं? तो आपकी यूनिवर्सिटी तो ऐसी है कि यहाँ पढ़े-लिखे भी अनपढ़ हो जाते हैं। (हँसी) स्पीकर सर, महिलाओं की शिक्षा के लिए अगले साल को हमने 'गर्ल ईयर चाइल्ड' ईयर डिक्लेयर किया है। इसके पीछे खास कारण है। इसमें हमने बहुत सारी कंसैशन भी दी हैं। जो बहन बेटियां पढ़ने जाती थी उनको बसों में यात्रा करने के लिए दस सिंगल फेयर देने पड़ते थे अब लड़कियों के लिए 5 सिंगल फेयर एक महीने के लिए देने पड़ेंगे। इस किस्म से कंसैशन दे रहे हैं। यूमैन यूनिवर्सिटी को हमने डिक्लेयर किया है। इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस बारे में हमारे साथी धर्मपाल जी मलिक ने भी कहा है और इनके पूरा इलाके से 50 गांवों ने प्रस्ताव करके भेजा है वहां 5 हजार लड़कियां स्टूडैंट हैं इसलिए प्रस्ताव आया है कि खानपुर में महिला यूनिवर्सिटी खोली जाए। हमें इस पर जिस प्रकार उन लोगों का रिसपौंस मिल रहा है यदि सब चाहेंगे तो हम पूरा विचार करेंगे कि महिला यूनिवर्सिटी खानपुर में खोलेंगे। इसी प्रकार से इन्दौरा जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कहा कि लोकायुक्त की एप्वांटमैंट हो गई है लेकिन किसी से कोई सलाह नहीं की गई। अरे, जब इस बात का नियमों में प्रावधान है तो फिर किससे सलाह की जाएगी? सलाह माननीय अध्यक्ष महोदय से की जाती है तो माननीय अध्यक्ष महोदय से सलाह की गई, विपक्ष का नेता हो तो उससे भी सलाह की जाती है लेकिन जब सदन में विपक्ष का नेता बनाया ही नहीं गया है तो सलाह किससे करेंगे? मुझे खुशी होती कि हमारे विपक्ष के साथी इन्दौरा जी और दूसरे सदस्य इस बारे में कोई रचनात्मक सुझाव देते लेकिन इनकी तरफ से कोई भी ऐसा सुझाव नहीं आया जिसमें हरियाणा के किसी भी वर्ग के हित की बात हो। हमने हर वर्ग के हित में काम करने का फैसला किया है। चाहे वह दलित वर्ग हो या दूसरे वर्ग हों, हमने हर वर्ग को कन्सेशन दिया है जैसे कि चर्चा यहां पर हाउस में अभी हुई है, हमने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में एक किताब छपवाई है जो सभी सदस्यों को दी जाएंगी, उसको

आप सब लोग पढ़कर देख लेना और फिर बताना कि सभी वर्गों के हितों के बारे में सरकार ने फैसला लिया है या नहीं? चाहे लोकायुक्त की नियुक्ति हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं देने की बात हो, चाहे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की बात हो, हमने सब वर्गों के बारे में इस किताब में चर्चा की है। जैसा कि चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कही है। हरियाणा का किसान आत्महत्या न करे इसी वास्ते हमने यह फैसला किया है कि जिन किसानों की जमीन सरकार द्वारा किसी भी काम के लिए ऐक्वायर की जायेगी तो उसके लिए फ्लोर रेट निर्धारित कर दिया है। इसी तरह से कोआप्रेटिव बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लोन की ब्याज दरें सरकार ने कम की हैं। इसके अलावा सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी स्कीमों पर विचार कर रही है ताकि किसान मजबूत हों और उसका मनोबल न गिरे। किसान हमारे देश और प्रदेश की बैकबौन हैं इसलिए इनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। इनका मनोबल पूरी तरह से बना रहे यही हमारी सरकार का प्रयास है क्योंकि किसान और मजदूर हितैषी पार्टी की यह सरकार है। झूठे वायदे और बातें करना बहुत आसान है लेकिन उनको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमने जो वायदे किए हैं उनको पूरा करके दिखाया है। झूठे वायदे तो विपक्षी साथियों के नेता करते रहे हैं कि हमारी सरकार आयेगी तो हम प्रदेश के लोगों को बिजली, पानी फ्री देंगे, हमारी सरकार आयेगी तो हम किसानों को यह देंगे, वह देंगे। क्या दिया भाई? कण्डेला काण्ड, दुलीना काण्ड में किसानों और दलितों के साथ क्या किया, यह सारा सदन जानता है। कई साल पहले यह चर्चा चली थी, पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर लोकदल पार्टी के नेता चौधरी देवी लाल और इनके नेता ने किसानों को कहा था कि हमारी सरकार ला दो, अगर हमारी सरकार आ जायेगी तो मैं सारे कर्जे माफ कर दूँगा और ऊपर लिख दूँगा कर्जे माफ और नीचे दस्तखत कर दूँगा 'देवीलाल'। मैं यह नहीं कहता कि उस समय कर्जे माफ नहीं किए गए, कर्जे माफ किए गये, यह रिकॉर्ड की बात है लेकिन कितने कर्जे माफ हुए? पूरे हरियाणा में केवल 2830 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए गये और उसके बदले दस साल तक राज करते रहे तथा लोगों को गुमराह करते रहे। लेकिन हमने एक कलम से ही एक बार में 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बकाया बिलों की राशि को माफ किया है। यह कोई आसान काम नहीं था और न ही यह हमारा कोई चुनावी वायदा था। इन्होंने बेरोजगारी की बात की। पिछली सरकार ने जब चुनाव होने में 6 महीने का समय रह गया तो इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। लेकिन वे पिछले 4-5 साल से कहां गये थे उस समय उन्होंने ये भत्ते क्यों नहीं दिए? हमारे सामने फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, हमने कोई वोट मांगने नहीं जाना है फिर भी हमने बिजली के बिल माफ किए क्योंकि यह हमारी जिम्मेवारी है और कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग की हितैषी है। हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ाया है। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जो बेरोजगार नान-ग्रेजुएट्स हैं उनको 300 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमने किया है ताकि उन नौजवानों का गुजारा चलता रहे। इसी प्रकार से इस सरकार ने जितने भी कार्य किये हैं वे इनकी तरह से जनता से वोट लेने के लिए नहीं किए हैं। और न ही लोगों को गुमराह करने के लिए किए बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए किए हैं। यह सरकार आगे भी लोगों की सेवा करती रहेगी। इसी

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

प्रकार से इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट एरिया के बारे में कहा गया। एस०सी०जैड की बात कही गयी। शमशेर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एस०सी०जैड में जो भी गांव आएं, उनके विकास की जिम्मेवारी भी उनकी होनी चाहिए। यह बात आलरेडी हमने कही हुई है कि जो भी एस०सी०जैड लगाएंगे, उसमें जो गांव आएंगे उनका विकास भी उनको करना पड़ेगा, उनके बच्चों को नौकरियां देनी पड़ेगी तभी हमें फायदा होगा और प्रदेश को फायदा होगा। प्रदेश के किसान को, प्रदेश के जवान को, प्रदेश के मजदूर को फायदा हो, हमें रोजगार उपलब्ध हों, बेरोजगारी का समाधान हो, यही लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं लेकिन इसमें मुझे आपके सहयोग की जरूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा। भाई राम कुमार गौतम जी कई बार ऐसी बात कह देते हैं। वे मेरे साथी हैं मुझे खुशी है कि वे ऐसी बात करते हैं। एक आध आदमी ऐसा होना चाहिए। रामकुमार गौतम जी इस हाउस में न होते तो हाउस को टीक लग जाती। ये कोई न कोई ऐसी बात निकाल कर ले आते हैं और कह देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा था कि मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कि 5 साल के अंदर हम हरियाणा को पूरे देश में नम्बर वन का प्रदेश बनाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पहलू पर हमें आप लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, आप सब लोग उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। अन्त में मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आपके सहयोग की मांग करता हूँ।

Mr. Speaker : Now, I put the amendment given notice of by Dr. Sushil Indora to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end namely :—

"But regret that no mention has been made in the Address regarding :—

1. The scheme of increasing the skill in labourers ;
2. The scheme to make agriculture economically profitable ;
3. The scheme to equalize 6% rate of interest for agriculture as being charged for other sectors;
4. Increase of capacity of accumulation of available water through rainfall and river;
5. The provision of subsidy to be given on fertilizer direct to the farmers ; and
6. Achieving target of power generation for making the State self-reliant."

(The motion was lost)

Mr. Speaker : Question is —

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha Assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 13th January, 2006 at 2.00 P.M.

The motion was carried.

रूल्ज कमेटी की रिपोर्ट मेज पर रखना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, I lay on the Table of the House the Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Buisness in the Haryana Legislative Assembly, as required under Rule 243 ibid.

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में संशोधनों की स्वीकृति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, as you know the House will adjourn sine die today itself, therefore, if the House approves the amendments recommended in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly by the Rules Committee which are laid on the Table of the House may be got published in the Gazette after the adjournement of the House sine die.

Is it the pleasure of the House ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Alright, the amendments recommended in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly by the Rules Committee which are laid on the Table of the House may be got published in the Gazette after the adjourment of the House sine die.

विधान कार्य—

दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of

[Shri Randeep Singh Surjewala]
Members) Amendment Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

वाक आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री द्वारा सदन की कार्यवाही में शामिल होने के विरुद्ध एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आउट करते हैं क्योंकि इनका नाम विवादास्पद धोल्कर प्रकरण में उजागर हुआ है।

(इस समय सदन में उपस्थित नैशनल लोक दल के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, The Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, The House is adjourned sine die.

17.01 Hours The Sabha then *adjourned sine die.

41117—H.V.S.—H.G.P., Chd.